

[2023] 7 एस. सी. आर 26

अखिल भारतीय न्यायाधीशों का संगठन

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(लिखित याचिका (सिविल) सं. 643/2015)

19 मई, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई,

वी. रामसुब्रमणियन और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

न्यायपालिका-जिला न्यायपालिका-वेतन, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति की आयु आदि पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एस. एन. जे. पी. सी./आयोग) की सिफारिशों - आदेश डी. टी. डी. के माध्यम से वेतन संरचना में संशोधन को स्वीकार कर लिया गया। 27.07.2022 - कुछ राज्यों और संघ द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को आदेश डी. टी. डी. के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। 05.04.2023 - वेतन के संबंध में सिफारिशों के लाभ

आई. डी. 1 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन के प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं-आवेदन करने के लिए 2.81 का गुणक

पेंशनभोगियों के लिए भी-आई. डी. 1 से पहले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए, संशोधित पेंशन अंतिम प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत होनी चाहिए-सभी क्षेत्राधिकारों में न्यायिक अधिकारियों के सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए-उच्च न्यायालय और सक्षम अधिकारी 3 महीने के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई विभिन्न सिफारिशों के अनुरूप नियम लाने के लिए-उच्च न्यायालयों, राज्यों और संघ द्वारा 4 महीने के भीतर अनुपालन शपथ पत्र रिकॉर्ड पर रखे जाने चाहिए। 27.07.2022 और 18.01.2023, वेतन के सभी बकाया को पहले से ही 30.06.2023 द्वारा साफ़ करने का निर्देश दिया गया था।

अनुपालन शपथ पत्र 30.07.2023 द्वारा दाखिल किए जाएँ-पेंशन की स्वीकृत संशोधित दरों का भुगतान 01.07.2023 से किया जाएगा-पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया भुगतान के लिए, आदेशों का पालन करते हुए। 27.07.2022 और 18.01.2023, 25 प्रतिशत आई. डी. 3 द्वारा भुगतान किया जाएगा, 25 प्रतिशत आई. डी. 2 द्वारा और शेष 50 प्रतिशत आई. डी. 1 द्वारा भुगतान किया जाएगा-वेतन और पेंशन पर आगे अनुपालन के लिए मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे।

न्यायपालिका-जिला न्यायपालिका-न्यायिक वेतन, पेंशन और भत्तों के लिए विकसित सिद्धांत-आयोजित किए गए: एक एकीकृत न्यायपालिका के लिए न्यायिक अधिकारियों के समान पदनाम और सेवा शर्तों की आवश्यकता होती है।

देश भर में-न्यायाधीश राज्य के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन हैं

26 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत का संघ

सार्वजनिक पद के धारक जो संप्रभु न्यायिक शक्ति रखते हैं-वे

केवल विधायिका के सदस्यों और कार्यपालिका में मंत्रियों की तुलना की जा सकती है-न्यायिक शाखा के अधिकारियों के साथ विधायी शाखा और कार्यपालिका शाखा के कर्मचारियों के बीच समानता का दावा नहीं किया जा सकता है-न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारियों का वेतन अकेले होना चाहिए और राजनीतिक कार्यपालिका या विधायिका के कर्मचारियों की तुलना में नहीं होना चाहिए-न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसमें जिला न्यायपालिका शामिल है, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है-एक स्वतंत्र न्यायपालिका तक पहुंच संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करती है-संविधान में सभी न्यायिक अधिकारियों का आवश्यक कार्य

जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के न्यायाधीश अनिवार्य रूप से एक ही हैं-चर्चा किए गए सिद्धांत-अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत भारत का संविधान-अनुच्छेद 125,221। -

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 सिफारिशों पर ध्यान देना

भुगतान पर

वेतन पर एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा की गई व्यक्तिगत सिफारिशें

अखिल भारतीय प्रारूप के अनुरूप न्यायिक अधिकारियों का I.Redesignation भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसलिए, न्यायाधीशों के पद पूरे देश में एक समान होने चाहिए। इस संबंध में,

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एफ. एन. जे. पी. सी.) ने सुझाव दिया

निम्नलिखित नाम पूरे भारत में अपनाया जाना है: आई. सिविल जज (जूनियर डिवीजन); सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग); iii. जिला न्यायाधीश। एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा की गई गहन जांच से पता चला है कि इन पदनामों में

इसे कुछ राज्यों में अपनाया नहीं गया है। इस सिफारिश को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के फैसले के आधार पर एफ. एन. जे. पी. सी. में स्वीकार कर लिया गया था। (II) V. भारत संघ। इस निर्देश का पालन उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाए और सभी उच्च न्यायालय एफ. एन. जे. पी. सी. और एस. एन. जे. पी. सी. के सुझावों के अनुरूप अपने पदनामों में संशोधन करें। यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा सुझाए गए वेतन मैट्रिक्स के आलोक में, समान पदनामों के बिना, विभिन्न राज्यों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पदनामों के फिटमेंट के लिए भविष्य में मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इस न्यायालय को ऐसी जटिलताओं से बचना चाहिए। अतः आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है।

नतीजतन, उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक अधिकारियों का पदनाम समान रूप से समान है। [पारस 42 45] [58-जी; 59-ए-ई]

II. वेतन मैट्रिक्स मॉडल के अनुसार नई वेतन संरचना

चूंकि एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिश केवल 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुरूप वेतन संरचना लाने के लिए है,

इन सिफारिशों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार, यह निर्देश दिया जाता है कि एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा सुझाए गए सुझावों को दर्शाते हुए न्यायिक अधिकारियों की वेतन संरचना को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए। [पैरा 46] [59-एफ-जी]

III. 2. 81 का गुणक और इसका समान अनुप्रयोग

उच्च न्यायालयों को 2.81 का गुणक दिया गया था, न्यायिक अधिकारियों को भी वही गुणक दिया जाना था। यह पिछले न्यायिक वेतन आयोगों द्वारा स्थापित मिसाल रही है और इस न्यायालय द्वारा बार-बार समर्थन किया गया। यह न्यायालय पहले ही राज्यों और संघ की आपत्तियों को खारिज कर चुका है और इसके परिणामस्वरूप राज्यों के गुणक/तर्कसंगतकरण के सूचकांक को स्वीकार कर चुका है।

2.81 आदेश दिनांक 27.07.2022 और आदेश दिनांक 05.04.2023 में एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा सुझाए गए युक्तिकरण के गुणक/सूचकांक को स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायिक अधिकारियों के वेतन को दिनांकित 27.07.2022 आदेश के साथ संलग्न तालिका-I के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। [पैरा 48 50] [60-सी-एफ]

IV. बढ़ोतरी

आयोग की सिफारिशें जहाँ तक वह पेंशन के उद्देश्यों के लिए वृद्धि प्रदान करता है

बता दें कि न्यायिक अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन जो वेतन वृद्धि देय होती है, उसे उसकी पेंशन की गणना में उसके अंतिम वेतन के रूप में शामिल किया जा सकता है, जो रुपये की ऊर्ध्वाधर सीमा के अधीन है। 2,24,100 / - . [पैरा 55] [61-जी; 62-ए-बी]

V. मास्टर पे स्केल से पे मैट्रिक्स सिस्टम में फिटमेंट और माइग्रेशन ऑल इंडिया जज एसोसिएशन V.

भारत का संघ

आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सूत्र और विधि की सिफारिश की कि मास्टर वेतनमान से वेतन मैट्रिक्स प्रणाली में स्थानांतरण सुचारू रूप से हो। आयोग ने तैयार किया है कि

फिटमेंट/माइग्रेशन सूत्र। इस सिफारिश को स्वीकार करते समय मार्च 2021 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित फिटमेंट/माइग्रेशन के लिए, उदाहरणों को प्रासंगिक नियमों का हिस्सा बनना चाहिए जिन्हें उच्च न्यायालयों, राज्यों और संघ द्वारा कूटबद्ध किया जाना आवश्यक है। इसलिए, सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है और अधिकारियों को इसे लागू करने का निर्देश दिया जाता है।

आयोग द्वारा दिए गए उदाहरणों को ध्यान में रखें। [पारस 56,59] [62-सी; 63-सी]

VI. 01.01.2016 से सिफारिशों का अनुप्रयोग

7 वाँ केंद्रीय वेतन आयोग 01.01.2016 से लागू हुआ। हालाँकि, न्यायिक अधिकारियों का अंतिम वेतन संशोधन 01.01.2006 से प्रभावी था। न्यायिक अधिकारियों को वेतन संशोधन प्राप्त हुए 17 साल से अधिक समय बीत चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए। वेतन के संबंध में सिफारिशों के लाभ 01.01.2016 से प्रभावी होने चाहिए। [पैरा 60] [63-ई-एफ]

VII. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर डीए

एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिश है कि महँगाई

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। महँगाई भत्ते की एक निश्चित दर यह भी सुनिश्चित करेगी कि न्यायिक अधिकारियों को महँगाई भत्ते के संचय में कोई देरी न हो। डीए की एक समान दर एकरूपता के साथ-साथ दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। ऐसी परिस्थितियों में,

सिफारिश स्वीकार किए जाने योग्य है। [पारस 62,63] [64-ई, जी; 65-ए]

VIII. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को प्रथम एसीपी का अनुदान

आयोग ने सुझाव दिया कि सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) को पहली आश्वस्त कैरियर प्रगति प्रदर्शन के शिथिल मानदंडों के आधार पर दी जानी चाहिए। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को प्रथम ए. सी. पी. का अनुदान आयोग के सुझावों के संदर्भ में उच्च न्यायालयों द्वारा तैयार किए गए नियमों में ढील के आधार पर दिया जाएगा। [पारस 64,69] [65-बी; 66-डी-ई] [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (III) v. भारत संघ, (2002) 4 एस. सी. सी. 247: [2002] 2 एस. सी. आर. 712; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (3) v. भारत संघ (2010) 15 एस. सी. सी. 170; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ। बी. भारत संघ (2022) 7 एससीसी

494 संदर्भित किया गया।

IX. ए. सी. पी. अनुदान में देरी
आयोग की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि कई मामलों में

राज्यों, ए. सी. पी. पैमाने के अनुदान में देरी हो रही है। एस. एन. जे. पी. सी. का यह निष्कर्ष कि ए. सी. आर. की समय पर तैयारी और जांच की कमी देरी का प्राथमिक कारण है, चिंताजनक है। एसीआरएस बाध्य हैं

समय पर और बिना किसी देरी के किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी न्यायिक प्रणाली कुशल तरीके से काम कर रही है। तदनुसार, उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा सकता है कि भविष्य में एसीआर बनाने में देरी से बचा जाए। भविष्य में इस देरी से बचने के लिए, आयोग ने सुझाव दिया कि ए. सी. पी. के अनुदान की प्रक्रिया उस तारीख से 3 महीने पहले शुरू की जानी चाहिए जिस दिन न्यायिक अधिकारी 5/10 वर्ष पूरे कर रहे होंगे और न्यायिक अधिकारी को वित्तीय लाभों का भुगतान न्यायिक अधिकारी के सेवा के 6वें/11वें वर्ष में कदम रखने के बाद 6 महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। इसलिए आयोग ने

सिफारिश की गई है कि यदि ए. सी. पी. के अनुदान में हर वर्ष देरी होती है, तो देरी के हर वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वृद्धि दी जाएगी।

ए. सी. पी. बकाया के साथ समायोजन के अधीन। आयोग की सिफारिशें उचित हैं। इस प्रकार, सिफारिश स्वीकार किए जाने के योग्य है। [पारस 70-73] [66-E-G; 67 A-C]

X. औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीशों को दिया जाने वाला वेतन संशोधन न्यायाधिकरण की सिफारिश कि वेतन संशोधन को औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों के न्यायाधीशों तक बढ़ाया जाए, स्वीकृति के योग्य है क्योंकि यह केवल इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का विस्तार। [पैरा 77] [68-सी ई]

केरल राज्य बनाम। बी. रंजीत कुमार, (2008) 12 एससीसी 219 [2008] 9 एससीआर 1078; महाराष्ट्र राज्य बनाम। श्रम कानून व्यवसायी और संगठन। , (1998) 2 एस. सी. सी. 688

: [1998] 1 एस. सी. आर. 793-निर्भर।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत का संघ

XI. महाराष्ट्र में पारिवारिक न्यायालयों में न्यायाधीश

आयोग की सिफारिश है कि परिवार न्यायालय के न्यायाधीश भी चयन के लाभ के हकदार होंगे।

ग्रेड और सुपर टाइम स्केल भी। आयोग आगे सिफारिश करता है कि आवास के सामान्य पूल से उन्हें क्वार्टर भी दिए जाएं। एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिश उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप है जो इस न्यायालय द्वारा केरल राज्य बनाम में निर्धारित किए गए हैं। बी. रंजीत कुमार और महाराष्ट्र राज्य बनाम। लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन श्रम न्यायालयों के लिए। जब न्यायिक अधिकारियों द्वारा समान काम किया जाता है, तो उनका वेतन और सेवा की शर्तें भी समान होनी चाहिए। अतः आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है। [पारस 79,80] [68-जी; 69-ए-बी]

बारहवीं। विशेष न्यायपालिका को न्यूनतम पारिश्रमिक

मजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी) और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट

सिफारिशें और उनके संशोधन/स्वीकृति

सारणीबद्ध है।

1.2 अनुशंसाओं पर विचार

पेन्सीयन, ग्रेजुटी ई. टी. सी.

I. 01.01.2016 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए पेंशन के प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं

आयोग ने किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है

पेंशन का वर्तमान प्रतिशत, पेंशन के लिए अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत और पारिवारिक पेंशन के लिए अंतिम वेतन के लिए 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। एफ. एन. जे. पी. सी. ने भी इस स्थिति की सिफारिश की थी और इस न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया था। इसलिए, जब किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की जाती है, तो सिफारिश के संबंध में कोई वास्तविक आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। [पैरा 86] [76-बी-सी]

II. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की संशोधित पेंशन अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

एफ. एन. जे. पी. सी. और एक व्यक्ति आयोग की राय पर विचार करने के बाद आयोग ने सिफारिश की कि

न्यायिक अधिकारी जो 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, संशोधित पेंशन सेवानिवृत्ति के समय आयोजित पद के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होना चाहिए। यह भी इसके निर्माण में अपरिवर्तित है और इस प्रकार वही रहता है। [पैरा 87] [76-डी]

III. वेतन मैट्रिक्स में पेंशनभोगियों का गुणक और फिटमेंट [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयोग की सिफारिश है कि 2.81 का गुणक पेंशनभोगियों पर समान रूप से लागू होगा और साथ ही वेतन में फिटमेंट पर सिफारिश के साथ, एस. एन. जे. पी. सी. ने मार्च 2021 की अपनी पूरक रिपोर्ट में फिटमेंट पर एक शुद्धिपत्र जारी किया है। यह शुद्धिपत्र अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करता है।

मूल रिपोर्ट। इसलिए, फिटमेंट टेबल को फिटमेंट पर सही किए गए टेबल के अनुसार समझा जाना चाहिए। गुणक जो वेतन पर लागू होता है, वह पेंशन पर भी लागू होना चाहिए। नतीजतन, पेंशनभोगियों को वेतन मैट्रिक्स में उसी योजना में फिट किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह सिफारिश स्वीकार की जाती है। [पारस 88-90] [76-E-F, G-H; 77-A]

IV. 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों का परिणामी पुनर्निर्धारण

आयोग ने नोट किया कि एक विसंगति के कारण

एक-व्यक्ति आयोग की रिपोर्ट, 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन को 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के बराबर नहीं दिया जा रहा था। आयोग की सिफारिश केवल समानता को आगे बढ़ाने के लिए है। राज्य

अतीत में सरकारों को पहले भी परिणामी पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है। हालाँकि, यदि इस तरह के परिणामी पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है, तो वे अधिकारी जो 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, और जिनकी उम्र काफी अधिक होगी, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। ऐसी स्थिति से बचा जाना चाहिए और इस प्रकार सिफारिश स्वीकार किए जाने के योग्य है। यह सिफारिश को तुरंत और बिना किसी देरी के लागू करने का निर्देश दिया जाता है। [पारस 91,92] [77-बी-सी, ई-एफ]

V. गणना करते समय बार में वर्षों के अभ्यास का लाभ

पेंशन यह सिफारिश, इस न्यायालय के फैसले का कार्यान्वयन होने के कारण, स्वीकृति के योग्य है। [पैरा 93] [78-बी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम अखिल भारतीय युवा वकील

एसोसिएशन (2009) 14 एस. सी. सी. 49: [2009] 3 एससीआर 555 -

पर भरोसा किया।

VI. पारिवारिक पेंशन पर सिफारिशें

जहाँ तक पारिवारिक पेंशन का संबंध है, आयोग ने नहीं किया है

मौजूदा प्रतिशत में किसी भी बदलाव की सिफारिश की गई है, अर्थात् 30 प्रतिशत अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V.

भारत का संघ

अंतिम निकाले गए वेतन से। इसलिए, यह सिफारिश, इस प्रकार, किसी भी आगे के विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह केवल

मौजूदा शासन की निरंतरता। यह है सिफारिश

इस प्रकार सिफारिश भी स्वीकार की जाती है क्योंकि यह केंद्रीय सिविल सेवाओं के सदस्यों को दी गई है। परिवार की मात्रा पेंशन के लिए लागू उसी गुणक/तर्कसंगतकरण के सूचकांक के अनुसार पेंशन में वृद्धि की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वही कारक जो वेतन और पेंशन पर लागू होते हैं जिससे उनकी वृद्धि होती है, वे पारिवारिक पेंशन पर भी समान रूप से लागू होते हैं। आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है। सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि पारिवारिक पेंशन की मात्रा भी उसी तरह तय की जाए जैसे पेंशन की मात्रा तय की जाती है। अंतिम सिफारिश यह है कि राज्यों द्वारा निर्धारित आय सीमा पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होना चाहिए। द.

आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा रु। 30,000 / - . यह सीमा उचित है लेकिन यह राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे एक उच्च सीमा निर्धारित करें जो न्यायिक अधिकारियों के लिए अधिक फायदेमंद हो। इस प्रकार, सिफारिश स्वीकार की जाती है। [पारस 94-97] [78-C-G]

से पेंशन की अतिरिक्त राशि के भुगतान की सिफारिश की गई 75 वर्ष की आयु के बाद। यह देखते हुए कि कई राज्यों ने 70 वर्ष की आयु से यह लाभ प्रदान किया और आयोग ने 75 वर्ष की आयु से पेंशन की अतिरिक्त मात्रा प्रदान करने की सिफारिश की। आयोग के इस तर्क को स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि राज्य अधिक लाभकारी पेंशन दरें दे रहे हैं, तो न्यायिक अधिकारियों को इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायिक अधिकारियों को राज्य के अधिकारियों से बदतर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, यह न्यायालय इस सिफारिश को स्वीकार करता है। आयोग ने आगे सिफारिश की है कि [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस लाभ का भुगतान 01.01.2016 से किया जाना चाहिए। वेतन और पेंशन के पहलुओं के लिए अन्य समान सिफारिशों के साथ, इस सिफारिश को स्वीकार किया जाता है। यदि न्यायिक अधिकारियों को पहले ही एक अधिक लाभकारी व्यवस्था प्रदान की जा चुकी है और उन्हें आयोग द्वारा सुझाए गए शासन में स्थानांतरित किया जाता है और न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो नहीं

उनके खिलाफ वसूली की जानी चाहिए। नतीजतन, यह राज्यों पर छोड़ दिया जाता है कि वे 75 वर्ष की आयु तक भी लाभ जारी रखें। इन सिफारिशों को तदनुसार स्वीकार किया जाता है। [पैरा

98 , 100-102] [78 - एच; 79-ए, सी-एफ]

VIII. ग्रेच्युटी पर सिफारिशें

आयोग द्वारा ग्रेच्युटी पर पहली सिफारिश

01.01.2016 से प्रभावी अनुशंसाएँ। द. सिफारिशें 01.01.2016 से लागू होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, वे न्यायिक अधिकारी जो बाद में सेवानिवृत्त हुए

01.01.2016 रिपोर्ट की स्वीकृति से भी लाभान्वित होना चाहिए।

इस प्रकार, आयोग ने सुझाव दिया है कि संशोधित अधिकतम सीमा के अधीन उन्हें अंतर उपदान का भुगतान किया जाए। यह केवल परिणामी है और इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। फाइनल

आयोग द्वारा इस विषय पर की गई सिफारिश उपदान यह है कि मृत्यु उपदान का भुगतान 7 वें सी. पी. सी. की तर्ज पर किया जाए। तदनुसार, सिफारिश स्वीकार की जाती है क्योंकि यह इस न्यायालय द्वारा पहले से ही स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप है। [पारस 103-106] [79-G-H; 80-A-D]

IX. के मामले में वित्तीय सहायता पर सिफारिशें

डेथ ऑल इंडिया जज एसोसिएशन v. भारत का संघ

आयोग ने सिफारिश की है कि यदि किसी न्यायिक अधिकारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान मृतक अधिकारी के जीवनसाथी/आश्रित को देय है। आयोग की सिफारिश सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के संदर्भ में है। यह सिफारिश उचित है और

सेवाओं में एकरूपता के सिद्धांत को आगे बढ़ाना। इसलिए, यह इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य है। [पैरा 108] [80-एफजी]

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (II) v. भारत संघ (1993) 4 एस. सी. सी. 288 [1993] 1 पूरक एससीआर 749; एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981 पूरक एस. सी. सी. 87: [1982] एस. सी. आर. 365; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। वी. भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: [1993] 2 पूरक एससीआर 659; 1998 का विशेष संदर्भ संख्या 1, पुनः (1998) 7 एस. सी. सी. 739: [1998] 2 पूरक एस. सी. आर. 400; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। वी. भारत संघ (2016) 5 एस. सी. सी. 1 [2015] 13 एस. सी. आर. 1; निदेशक, के. पी. टी. सी. एल. बनाम। सीपी

मुण्डिनामानी (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 401; अनीता कुशवाहा बनाम। पुष्प सूडान (2016) 8 एस. सी. सी. 509: [2016]

9 एस. सी. आर. 560-पर निर्भर।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ। वी. भारत संघ (2019) 12 एस. सी. सी. 314; बृज मोहन लाल बनाम। भारत संघ (2012) 6 एससीसी 502: [2012] 5 एस. सी. आर. 305; हुसैनारा खातून (1) बनाम। गृह सचिव। , बिहार राज्य (1980) 1 एस. सी. सी. 81: [1979] 3 एस. सी. आर. 169; दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाम। पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (1996) 6 एस. सी. सी. 323: [1996] 7 पूरक एस. सी. आर. 432; मो. हुसैन बनाम। सरकार. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2012) 9 एस. सी. सी. 408: [2012] 10 एस. सी. आर. 480; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ (2010) 14 एससीसी

720 ; नंद विजय सिंह बनाम। भारत संघ (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 1090; बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड v. इसके कर्मचारी (1969) 2 एस. सी. आर. 113; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ। वी. भारत संघ (2014) 14 एस. सी. सी. 444; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ। वी. भारत संघ डब्ल्यू. पी. (सी) No.1022/1989 आदेश दिनांक 14.07.2016; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ वी. भारत संघ डब्ल्यू. पी. (सी) No.1022/1989 दिनांकित आदेश

13.03.2018 - संदर्भित किया गया।

23]

राष्ट्रमंडल पूर्व रिले कैरोल बनाम टेट, 274 ए. 2 डी। 19
संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1993] 1 पूरक। एससीआर 749

उस पर भरोसा करें

पैरा 1,1

25 , 27

&

पैरा 2,

[2002] 2 एससीआर 712

संदर्भित किया गया है

(2010) 15 एससीसी 170

पैरा 3,6

संदर्भित किया गया है

(2019) 12 एस. सी. सी. 314

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[2012] 5 एससीआर 305

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1982] एससीआर 365

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[1998] 2 पूरक। एससीआर 400

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[2015] 13 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[1979] 3 एससीआर 169

पैरा 32

संदर्भित किया गया है

[1996] 7 पूरक। एससीआर 432

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[2012] 10 एससीआर 480

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[2016] 9 एससीआर 560

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

(2010) 14 एससीसी 720

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

(1969) 2 एससीआर 113

संदर्भित किया गया है

पैरा 62

(2022) 7 एससीसी 494

पैरा 67

संदर्भित किया गया है

पैरा 77,

[2008] 9 एससीआर 1078

उस पर भरोसा करें

पैरा 77,

[1998] 1 एससीआर 793

उस पर भरोसा करें

(2014) 14 एस. सी. सी. 444

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

[2009] 3 एससीआर 555

उस पर भरोसा करें

पैरा 93

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सी. आई. वी.

2015 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

सभी भारत न्यायाधीशों के संगठन के साथ V. भारत का संघ

2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) Nos.6471-6473 और

2015 की लिखित याचिका (सिविल) No.643 में 2022 की अवमानना याचिका (सिविल) Nos.711,2023 की 36,37,38,39,40,848

कुलदिप परिहार, डिप्टी ए. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., बी. के. सतीजा, हेमंत गुप्ता, बरुण कुमार सिन्हा, निखिल गोयल, नचिकेता जोशी, गौरव धामा, अमित आनंद तिवारी, A.A.Gs, गौरव बनर्जी, पी. विश्वनाथ शेटी, वी. गिरि, जयदीप गुप्ता, संजय पारिख, विनोद घई, डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. परमेश्वर, (न्यायमित्र), सुश्री मयूरी रघुवंशी, वी. पी. सिंह, व्योम रघुवंशी, सुश्री आकांक्षा राठौर,

सुश्रो, मिलिंद कुमार, दीपक प्रकाश, वी. एन. रघुपति, वसीम कादरी, मोहम्मद अखिल, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, राजन कुमार चौरसिया, अरविंद कुमार शर्मा, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, अनमोल चंदन,

वत्सल जोशी, अनिरुद्ध शर्मा-(ii), ईशान शर्मा, डॉ. एन. विशाखमूर्ति, कानू अग्रवाल, भुवन कपूर, सुश्री इंदिरा भाकर, मुकेश के. वर्मा, गुरमीत सिंह मक्कर, राज बहादुर यादव, अमरीश कुमार, महेश ठाकुर, सुश्री गीतांजलि बेदी, सुश्री विपाशा सिंह, सुश्री शिवानी, गोपाल झा, सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, अभिषेक मोहंती, सुधांशु एस. चौधरी, महेश पी. शिंदे, सुश्री रुचा ए. पांडे, एम. वीरारागवन, संदीप

सुधाकर देशमुख, निशांत शर्मा, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, रोहित बंसल, सुश्री क्षितिज सिंह, अपूर्व कुरुप, सुश्री कीर्ति दधीच, ओजस्वा पाठक, सुश्री कविता झा, जेम्स पी. थॉमस, रवि सागर, पी. आई. जोस, नरेश के. शर्मा, संजय कुमार पाठक, अरविंद कुमार त्रिपाठी, श्रीमती शशि पाठक, निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, सुश्री प्रगति नीखरा, आदित्य भानु नीखरा, निशांत कुमार, सुनंदो सर, अनुपम रैना, कृष्णानंद पांडे, हर्षित गुप्ता, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, लिखी चंद बोन्सले, राहत बंसल, सुश्री कोमल मुंद्रा।

नायर, ए. राधाकृष्णन, अर्जुन गर्ग, आकाश नंदोलिया, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, सिबो शंकर मिश्रा, श्रीमती प्रभावती नायक, निरंजन साहू, देवव्रत दास, सुश्री अपूर्व शर्मा, अशोक माथुर, मुकुल कुमार, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, मेसर्स। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, मुकेश के. गिरि, महफूज अहसान नाज़की, पोलांकी गौतम, केवी गिरीश चौधरी, टी. विजया भास्कर रेड्डी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, सुश्री नीति रिचरिया, शुभदीप रॉय, साई शशांक, दीपायन दत्ता, मनीष कुमार, सुमीर सोधी, देवाशीष तिवारी, गौरव अरोड़ा, सुश्री सुजाता कुर्दुकर, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री पायल गुप्ता, समर विजय सिंह, शिवांग जैन, सुश्री प्रीति चौहान, सुश्री पूर्वा, अरुण कुमार जयसवाल, केशव मित्तल, सुश्री अमृता वर्मा, सुश्री सबर्नी सोम, सुश्री प्रतिष्ठा विज,

श्रीवास्तव, शैलेश मडियाल, वैभव सभरवाल, अक्षय कुमार, राजीव [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शंकर द्विवेदी, आनंदो मुखर्जी, श्वेतांक सिंह, वी. एन. रघुपति, मनेन्द्र पाल गुप्ता, श्रीमती अंशा वर्मा, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के जाँय, आलिम अनवर, सुश्री मनिका प्रिया, रिद्धी बोस, सनी चौधरी, अंकित मिश्रा, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत बागला, सुश्री श्रेया सक्सेना, सुश्री यामिनी सिंह, सौरव सिंह, पुखरंभम रमेश कुमार, करुण शर्मा, ऋत्विक् पारिख, सुश्री अनुपमा नगंगोम, अविजीत मणि त्रिपाठी, निर्णमेश दुबे, सिद्धेश।

कोतवाल, सुश्री एना उपाध्याय, सुश्री मान्या हसीजा, निहार धर्माधिकारी, सुश्री के. एनाटोली सेमा, सुश्री लिमायिनला जमीर, अमित कुमार सिंह, सुश्री चुबलेमला चांग, प्रांग न्यूमाई, शिवाशीष मिश्रा, अजय पाल, मयंक दहिया, सुश्री सुगंध राठौर, सुश्री शुभांगी अग्रवाल, समीरा।

अभ्यंकर, सुश्री वाणी वंदना छेत्री, सुश्री निशी संगतानी, सुश्री सुगंध राठौर, शबरीश सुब्रमण्यन, सुश्री देवयानी गुप्ता, विष्णु

उन्नीकृष्णन, नमन द्विवेदी, दानिश सैफी, सी क्रांति कुमार, श्रीहर्ष पीचारा, राजीव कुमार चौधरी, सुश्री पल्लवी, दुव्वुरी सुब्रमण्य भानू, संजय कुमार त्यागी, संजय कुमार, सुनील कुमार तोमर, पवन, सुदर्शन सिंह रावत, सुश्री रचना गांधी, पारिजात सिन्हा, सुश्री। मधुमिता भट्टाचार्य, सुश्री उर्मिला कर पुरकायस्थ, अन्नंत, सुश्री आरुषि मिश्रा, पराग एम. श्रॉफ, अरविंद एस., सुश्री उमा भुवनेश्वरी सी., अब्बास, श्रीमती अंजनी अय्यगारी, अंकुर कश्यप, रोहित राजर्षि, अमन बजाज, गोपाल झा, गौरव अग्रवाल, उदय वी. दुबे, सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री कांति, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

सूचकांक *

कमीशन का भुगतान करने की शुरुआत

..... 4

1 .

एस. एन. जे. पी. सी. की रिपोर्ट और इस न्यायालय के आदेश। 5

2 .

वकील की प्रस्तुतियाँ।

..... 7

3 .

4 .

न्यायिक वेतन, पेंशन के लिए सिद्धांत विकसित
और भत्ते।

..... 10

I. पदनामों और सेवाओं में एकरूपता
शर्तें

... 10

II. शक्तियों का पृथक्करण और उनके साथ तुलना

..... 11

राजनीतिक कार्यपालक

* एड। ध्यान दें: तालिका में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

डिया जज एसोसिएशन V. भारत का संघ

III. जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसका हिस्सा है बुनियादी संरचना 15

IV. न्यायिक स्वतंत्रता और उन तक पहुँच

न्याय भाग III के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है संविधान से। 16

V. जिले के न्यायिक कार्यों की समानता

न्यायपालिका और उच्च न्यायपालिका.. 17

वेतन पर सिफारिशें। 18

एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिशों पर इस न्यायालय के आदेश

..... . 21

भुगतान करें।

वेतन पर सिफारिशों पर विचार। 21

I. अनुरूपता में न्यायिक अधिकारियों की पुनः नियुक्ति

अखिल भारतीय पैटर्न के साथ (अनुशंसा)

44.1) 21

मॉडल (अनुशंसा 44.2,44.3). 22 III. 2. 81 का गुणक और इसकी वर्दी

आवेदन (अनुशंसाएँ 44.4-44.6)।

IV. वृद्धि (अनुशंसा 44.7,44.11). 24

V. मास्टर पे स्केल से फिटमेंट और माइग्रेशन

मैट्रिक्स प्रणाली का भुगतान करना (सिफारिशें 44.8, ... 25

44.9 , 44.10) VI. से सिफारिशों का अनुप्रयोग

01.01.2016 (अनुशंसा 44.12). 26

VII. आदेश में निर्देशों के अनुपालन की स्थिति

दिनांक 27.07.2022 (का संशोधन) अनुशंसा सं. 44.13)।

एस. सी. ई

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर VIII.DA (अनुशंसा 44.14)। 27

IX. सिविल जज को प्रथम ए. सी. पी. का अनुदान (जूनियर डिव) (अनुशंसा 44.15 (i))।
... ..

28

ए. सी. पी. के अनुदान में देरी (अनुशंसा)

44.15 ((ख))।

..... 30

.....

XI. जिले के प्रतिशत में परिवर्तन न्यायाधीश (चयन श्रेणी) और जिला न्यायाधीश
(सुपर टाइम स्केल) (अनुशंसा 44.16). 30

बारहवीं। पीठासीन को वेतन संशोधन दिया जाएगा औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम के न्यायाधीश
अदालतें (अनुशंसा 44.19)

..31

पारिवारिक न्यायालयों में XIII.Judges

..... 32

महाराष्ट्र (अनुशंसा 44.18)।

XIV। न्यूनतम पारिश्रमिक से लेकर विशेष तक न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी) और
विशेष महानगर मजिस्ट्रेट

.....

.....32

(अनुशंसा 44.19)।

पेंशन, ग्रेच्युटी और पेंशन पर सिफारिशें

37

सेवानिवृत्ति की आयु आदि।

अनुशंसाओं पर विचार

46

पेंशन, ग्रेच्युटी आदि।

I. सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन के प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं

01.01.2016 पर या उसके बाद (अनुशंसा)

39.1)

40

II. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की संशोधित पेंशन चाहिए।

अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होना

40 डिया जज एसोसिएशन v. भारत का संघ

वेतन मैट्रिक्स (अनुशंसा संख्या 39.3,39.4)। 41.
पुनर्निर्धारण

जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे

..... 41

(अनुशंसा सं। 39. 5)

वी. बार में अभ्यास के वर्षों का लाभ

पेंशन की गणना (अनुशंसा)

नहीं। 39.6)

.....

..... 42

VI. पारिवारिक परिवार पेंशन पर सिफारिशें

(अनुशंसा सं। 4. 1 से 4.4)। 42

VII. अतिरिक्त मात्रा पर सिफारिशें

पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अनुशंसा)

नं. 21.1 21. 4)।

43

VIII. ग्रेच्युटी पर सिफारिशें (अनुशंसा)

नं. 21.1 21. 4 तक)।

44

IX. सेवानिवृत्ति की आयु. 45 पर सिफारिशें

X. वित्तीय सहायता पर सिफारिशें

मौत का मामला

..... 45

XI. सहायता के लिए सिफारिशें

..... 45

पेंशनभोगी।

XII.Recommendations नए के उन्मूलन पर

..... ..46

पेंशन योजना।

अनुक्रमिक दिशाएँ।

..... 50

... ..

【 इधिंगंतम श्री नरसिम्हा, जे.

1. आयोगों को भुगतान करने के लिए परिचय

जिला न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली की रीढ़ है न्यायिक अधिकारी की स्वतंत्रता न्यायिक प्रणाली है:

यदि यह न्यायालय जिला न्यायपालिका को 'अधीनस्थ न्यायपालिका' के रूप में संदर्भित करता है

एक गलत नाम है क्योंकि जिला न्यायाधीश स्वयं एक के अधीनस्थ नहीं है

उसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग लेकिन संविधान [2023] 7 एस. सी. आर. का अनादर भी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिला न्यायपालिका में सेवारत। उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, उनकी वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के आग्रह पर, इस न्यायालय ने 1993 में यह कहने की आवश्यकता पाई कि एक न्यायिक वेतन आयोग होना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली लागू है, कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र है और उनके वेतन और सेवा शर्तों में न्यायपालिका की अपनी बात है। 2

2. इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक

वेतन आयोग ("एफ. एन. जे. पी. सी.") का गठन भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। एफ. एन. जे. पी. सी. की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.

जगन्नाथ शेटी ने 11.11.1999 पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस व्यापक रिपोर्ट में वेतन, पेंशन और भत्तों के साथ-साथ जिला न्यायपालिका से संबंधित अन्य सेवा शर्तों पर सिफारिशें शामिल थीं। लंबी कार्यवाही के बाद, 21.03.2002 पर, इस न्यायालय ने वेतन से संबंधित FNJPC की सिफारिशों को मंजूरी दे दी

भत्तों से संबंधित कुछ संशोधन। 3 विशेष रूप से, सिफारिशों को 01.01.1996 से स्वीकार किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उस तारीख से 5 वें केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ दिया गया था।

3. अगले कुछ वर्षों के भीतर, केंद्र सरकार ने नियुक्त किया

जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2010 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया था। 4 इस आयोग द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान, जो वर्तमान में लागू हैं, को 01.01.2006 से प्रभावी बनाया गया था। जिला न्यायाधीश का पद। हमारा संविधान एक जिला न्यायाधीश को न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है। इस संस्था और देश के लिए इसके योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए।

यह भी देखें, उपेंद्र बक्शी, न्यायपालिका

भारतीय लोकतंत्र के लिए एक संसाधन के रूप में,
भारत संगोष्ठी,

नवंबर 2010-पर उपलब्ध है

[HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. भारत-सेमिनार।com/2010/615](https://डब्ल्यू. डब्ल्यू. भारत-सेमिनार।com/2010/615)

615_उपेंद्र बक्शी। एचटीएम 2 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (II) v. भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 288। 3 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (III) v. भारत संघ, (2002) 4 एस. सी. सी. 247। 4 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (3) v. भारत संघ (2010) 15 एस. सी. सी. 170.

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

2. एस. एन. जे. पी. सी. की रिपोर्ट और आदेश

यह न्यायालय

4. दस साल बाद, 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। 01.01.2016 से प्रभावी सरकार। तदनुसार, वर्तमान में

रिट याचिका, एक बार फिर अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के कहने पर, इस न्यायालय से हस्तक्षेप करने और न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों को अद्यतन/उन्नत करने के लिए कहा गया है।

5. यह न्यायालय डब्ल्यू. पी. में दिनांकित 09.05.2017 आदेश द्वारा। (ग) सं. 643/2015 के नेतृत्व में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति पी. वी. रेड्डी (सेवानिवृत्त) को इसके अध्यक्ष के रूप में और वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत (पूर्व न्यायाधीश) को इसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया। इस माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार, भारत सरकार ने अपने संकल्प दिनांक 10.11.2017 द्वारा दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ("आयोग/SNJPC") का गठन किया। प्रस्ताव के अनुसार, आयोग के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

(क) देश भर में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित न्यायिक अधिकारियों के वेतन और अन्य परिलब्धियों की संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विकसित करना।
(ख) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के लिए उपलब्ध लाभों के कुल समूह को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन और सेवा की शर्तों की वर्तमान संरचना की जांच करना और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों जैसे पेंशन आदि सहित उपयुक्त सिफारिशें करना।

वेतन में मौजूदा सापेक्षताओं के लिए अन्य प्रासंगिक कारक

अधीनस्थ से संबंधित अधिकारियों के बीच संरचना

न्यायिक सेवाएँ बनाम अन्य सिविल सेवक और तंत्र

इस संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए।

(ग) कार्य विधियों और कार्य वातावरण की जांच करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के भत्ते और लाभ जो न्यायिक अधिकारियों को वेतन के अलावा उपलब्ध हैं और सुझाव देने के लिए।

इसे युक्तिसंगत बनाना और सरल बनाना

न्यायिक प्रशासन में दक्षता को बढ़ावा देना, न्यायपालिका के आकार को अनुकूलित करना आदि और न्यायपालिका में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करना।

पूर्व की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

5 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ। वी. भारत संघ, (2019) 12 एस. सी. सी. 314 '। न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 19018/01/2017 दिनांक 16.11.2017 के माध्यम से अधिसूचित।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(घ) ऐसी अंतरिम राहत पर विचार करना और उसकी सिफारिश करना जो सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी श्रेणियों के न्यायिक अधिकारियों के लिए उचित और उचित हो। अंतरिम राहत, यदि अनुशंसित है, तो इसके खिलाफ पूरी तरह से समायोजित करना होगा और

पैकेज में शामिल जो स्वीकार्य हो सकता है

की अंतिम सिफारिशों पर न्यायिक अधिकारी

आयोग।

वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए तंत्र अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्य समय-समय पर

विशेष रूप से गठित स्वतंत्र आयोग

ऐसे आयोग का उद्देश्य और संरचना होनी चाहिए

न्यायपालिका की ओर से पर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

6. आयोग की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इसने गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, लखनऊ, भोपाल, विशाखापत्तनम और श्रीनगर शहरों में क्षेत्रवार परामर्श सम्मेलन आयोजित किए, जहां अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ, अखिल भारतीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश संघ, राज्य संघों, रजिस्ट्री के अधिकारियों और उच्च न्यायालयों के प्रतिनियुक्त अधिकारियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ लंबे समय तक विचार-विमर्श किया गया। रिपोर्ट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि आयोग ने कार्यपत्रक और गणना तैयार करते समय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अभ्यावेदनों का विश्लेषण किया है और समय-समय पर कई विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया है।

7. व्यापक विचार-विमर्श के बाद, आयोग ने न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम राहत देने की आवश्यकता महसूस की क्योंकि उनके वेतन में 10 साल से अधिक समय से वृद्धि नहीं की गई थी। इस प्रकार, उन्होंने इस न्यायालय 09.03.2018 को अंतरिम राहत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह देखते हुए कि न्यायिक

अधिकारी अद्यतन/उन्नत वेतन के बिना थे, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा राज्यों और भारत संघ को अंतरिम राहत के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया।

8. इसके बाद, 29.01.2020 पर, आयोग ने अपना अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत किया

इस न्यायालय को रिपोर्ट करें। रिपोर्ट में सिफारिशें हैं जिनमें वेतन संरचना (खंड I), पेंशन और परिवार पेंशन (खंड III) और भत्ते (खंड IV) शामिल हैं। रिपोर्ट का एक अलग हिस्सा, भाग II जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के विषयों को निर्धारित करने के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करने के मुद्दे से संबंधित है।

9. इस न्यायालय ने 28.02.2020 पर रिपोर्ट का संज्ञान लिया। न्यायालय की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किए गए थे।

द स्टेट्स ऑल इंडिया जज एसोसिएशन V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

और भारत संघ को निर्देश दिया गया कि वे रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, दर्ज करें। न्यायालय ने कहा कि वर्षों से, जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न निर्देशों के कार्यान्वयन पर प्राथमिक आपत्ति वित्तीय संसाधनों की कथित कमी है, और राज्यों द्वारा उठाए जाने से पहले ही इस आपत्ति को खारिज कर दिया।

यह।

3. परामर्श की प्रस्तुतियाँ

10. न्यायमित्र, के. परमेश्वर ने रखा

आयोग की सिफारिशें और इस न्यायालय के समक्ष उसका तर्क। न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुतियों के विस्तृत नोट दाखिल किए गए हैं जो सिफारिशों को सारणीबद्ध करते हैं और उनके साथ पूरक हैं।

अतिरिक्त तर्क। उन्होंने राज्यों और केंद्र द्वारा रखी गई आपत्तियों को भी विस्तार से बताया और स्पष्टता के साथ उनका खंडन किया।

11. न्यायमित्र ने उन सिद्धांतों पर भी जोर दिया जिन पर आयोग की सिफारिशों को बल मिलता है। उन्होंने व्यापक रूप से न्यायालय के विचार के लिए पाँच सिद्धांतों का सुझाव दिया। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णयों ने अब तक केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को मान्यता दी है और

प्रस्तुत किया कि यह सिद्धांत जिला न्यायपालिका पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

12. इसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत संविधान के भाग III का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि यह एक निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी सुनिश्चित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक गारंटी के रूप में देखा जाना चाहिए।

संविधान।

13. तीसरा सिद्धांत, उनके प्रस्तुतिकरण में, अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत था, जैसा कि इस न्यायालय ने बृज मोहन लाल बनाम में देखा था। संघ

भारत सरकार, (2012) 6 एस. सी. सी. 502 और न्यायिक प्रभाव आकलन पर कार्य बल की रिपोर्ट (न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में) द्वारा सुझाए गए सुझाव के अनुसार न्यायपालिका को अपनी संवैधानिक रूप से अनिवार्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उचित राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर करना होगा। इसके लिए, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 50 पर भी भरोसा किया जो यह आदेश देता है कि "राज्य न्यायपालिका को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा"।

14. इसके बाद उन्होंने समीक्षा कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 05.04.20237 आदेश पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि एक

' इसके बाद, "आदेश की समीक्षा करें"।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक अधिकारियों के बीच मुख्य न्यायिक कार्य की समानता

प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि समान रूप से होनी चाहिए जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतन में वृद्धि को दर्शाता है।

15. अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली में, सेवा की शर्तें, पदनाम आदि पूरे देश में समान होने चाहिए। वह.

75 वर्ष की आयु से यह तर्क देते हुए दिया जाए कि यह न केवल उचित है, बल्कि कई राज्यों द्वारा पहले से ही और भी कम आयु से दिया गया है। इस संबंध में, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तुलना में कम है और इसलिए, वे किसी भी समय सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होने चाहिए। कम उम्र।

17. अखिल भारतीय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ओर से दलीलें

एस. एन. जे. पी. सी. की रिपोर्ट का कार्यान्वयन, विशेष रूप से सेवानिवृत्त अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन के संबंध में। 18. प्रतिवाद का नेतृत्व एल. डी. के. एम. नटराज ने किया। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो उत्तर राज्य की ओर से पेश हुए

प्रदेश। उनके साथ अमित आनंद तिवारी, ए. ए. जी. ने भी काम किया। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश राज्य की वकील सुश्री प्रतिष्ठा विज, महाराष्ट्र राज्य के वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी,

नचिकेत जोशी, मध्य प्रदेश राज्य के वकील, अजय पाल, पंजाब राज्य के वकील, मधुमिता भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल राज्य के वकील, शवोदीप राँय, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के वकील बनाम।

भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

असम, शैलेश मडियाल, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के वकील, पुखरंभम रमेश कुमार, मणिपुर राज्य के वकील, दीपानविता प्रियंका, गुजरात राज्य की ओर से पेश वकील, बी. के. सतीजा, हरियाणा राज्य के एएजी, कुलदिप सिंह परिहार,

राज्यों की ओर से उपस्थित उत्तराखंड राज्य के वकील। 19. उन्होंने सबसे पहले तर्क दिया कि 2.81 का गुणक सभी कैडरों में जिला न्यायपालिका पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह उनका तर्क है।

न्यायिक अधिकारी को उनकी सेवानिवृत्ति के बावजूद, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उनके राज्य में लागू नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए इस तरह के संचय का प्रावधान नहीं करते हैं, इसलिए यह न्यायिक अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता है। राज्यों ने एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा सुझाए गए सेवानिवृत्ति उपदान के अनुदान का भी विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके राज्य नियम जो प्रचलित हैं, राज्य में सभी संवर्गों और सेवाओं के लिए एक समान दर प्रदान करते हैं और इसलिए, उनके द्वारा सिफारिश स्वीकार नहीं की जा सकती है। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि पारिवारिक पेंशन के लिए न्यूनतम पात्रता रुपये से कम होनी चाहिए। 30,000 , आयोग के सुझाव के अनुसार।

20. वेतन, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति की आयु आदि पर एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिशों पर विचार करने से पहले न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक है जिनका सिफारिशों पर हमारे निर्णय पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

4. न्यायिक भुगतान, पेंशन के लिए प्रिंसिपल विकसित किए गए

और अनुमतियाँ

21. इस न्यायालय ने तीन अलग-अलग न्यायिक वेतन आयोग के साथ काम किया है और कुछ सिद्धांत विकसित किए हैं, जो न्यायिक वेतन, पेंशन और भत्तों को आधार बनाते हैं। पहला सिद्धांत यह है कि एक एकीकृत न्यायपालिका के लिए समान पदनाम और सेवा की आवश्यकता होती है

देश भर में न्यायिक अधिकारियों की शर्तें। दूसरा सिद्धांत यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारियों का वेतन स्थायी होना चाहिए और राजनीतिक कार्यपालिका या विधायिका के कर्मचारियों की तुलना में नहीं होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसमें जिला न्यायपालिका शामिल है, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। चौथा सिद्धांत [2023] 7 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका तक पहुंच संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करती है। पाँचवाँ सिद्धांत यह है कि जिला न्यायपालिका में सभी न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के न्यायाधीशों का आवश्यक कार्य अनिवार्य रूप से समान है।

I. Uniformity पदनाम और सेवा शर्तों में

22. भारत में इस योजना के तहत एक एकीकृत न्यायपालिका है

न्यायपालिका के उच्च स्तर के कामकाज को बनाए रखने के लिए सही प्रोत्साहन और पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 23. अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (II) में इस न्यायालय ने कानून की स्थिति पर ध्यान दिया है और कहा है कि समान सेवा शर्तों के साथ समान पदनाम और पदानुक्रम अपरिहार्य हैं।

परिणाम। यह आयोजित किया गया था:

" 14 .

दूसरा, इस देश में न्यायपालिका एक एकीकृत है।

न्यायिक रूप से संस्था, हालांकि प्रशासनिक रूप से नहीं। इसलिए

समान सेवा के साथ समान पदनाम और पदानुक्रम परिस्थितियाँ अपरिहार्य आवश्यक परिणाम हैं। द.

इसलिए दिए गए आगे के निर्देशों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यपालिका की शक्तियों पर अतिक्रमण के रूप में और

न्यायपालिका की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए विधायिका।

II. शक्तियों का पृथक्करण और राजनीतिक के साथ तुलना
कार्यपालक

24. शक्तियों के पृथक्करण की मांग है कि के अधिकारी

न्यायपालिका के साथ विधायी और कार्यकारी शाखाओं के कर्मचारियों से अलग और अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि न्यायाधीश राज्य के कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि वे सार्वजनिक पद के धारक होते हैं जिनके पास संप्रभु न्यायिक शक्ति होती है। उस अर्थ में, वे केवल सदस्यों के साथ तुलनीय हैं

विधायिका और कार्यपालिका में मंत्री। इस प्रकार, अधिकारियों के साथ विधायी शाखा और कार्यकारी शाखा के कर्मचारियों के बीच समानता का दावा नहीं किया जा सकता है।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (II) v. भारत संघ (1993) 4 एस. सी. सी. 288 पैरा 14 पर।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

न्यायिक शाखा। यह न्यायालय अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में है। (II) V. संघ भारत के, 'ने भेद को समझाया और कहा कि जो व्यायाम करते हैं

राज्य की शक्ति मंत्री, विधायक और न्यायाधीश हैं,

और न कि उनके कर्मचारियों के सदस्य जो लागू करते हैं या सहायता करते हैं अपने निर्णयों को लागू करें। इस प्रकार, कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि

न्यायिक अधिकारियों को ऐसा वेतन मिलता है जो कार्यकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं होता है। इस संदर्भ में यह भी याद रखा जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 50

राज्य को न्यायपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है कार्यकारी।

25. यह अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता

कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका की आवश्यकता होती है

उनके वित्त के मामलों में कहें। इस न्यायालय ने पहले उल्लेख किया है कि

सैद्धांतिक रूप से, कार्यपालिका को न्यायपालिका का वेतन तय करने की अनुमति देना।

इसके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। 10 इसलिए, सत्य को सुरक्षित करने के लिए

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इस न्यायालय ने मान्यता दी है कि

न्यायिक अधिकारी राज्य की अन्य शाखाओं के कर्मचारियों के वेतन से अलग और अलग होते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि एक अभिव्यक्ति है

अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। यह सिद्धांत आदेश देता है कि न्यायपालिका उन राशियों के भुगतान के लिए मजबूर करने की अंतर्निहित शक्ति होनी चाहिए

ऐसा धन जो इसे पूरा करने के लिए उचित और आवश्यक हो। अनिवार्य जिम्मेदारियाँ, और प्रशासन के लिए इसकी शक्तियाँ और कर्तव्य

न्याय "। यह सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण का केवल तार्किक निष्कर्ष है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है।

26. राज्यों की इस दलील की कि वित्तीय संसाधनों की कमी है, मामले के इस पहलू से जांच की जानी चाहिए। राज्यों ने

और संघ ने बार-बार कहा है कि वित्तीय पर बोझ

एस. एन. जे. पी. सी. की रिपोर्ट के कारण राज्यों/संघ के संसाधन हैं

यह महत्वपूर्ण है और इसलिए रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बिना

अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत, न्यायपालिका का कोई भी वित्तपोषण नहीं हो सकता है। दूर किया जाए।

¹ अखिल भारतीय न्यायाधीशों की पीठा (II) v. भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 288 पैरा 7 पर।

10 अखिल भारतीय न्यायाधीशों के संगठन में। (II) v. भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 288 पैरा 10: उस ओर से न्यायपालिका को किसी भी भूमिका से वंचित करना संविधान की भावना के खिलाफ होगा, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका या विधायिका के लिए उक्त शक्ति का उपयोग करके न्यायपालिका की पूंछ को मोड़ना और मोड़ना असंभव नहीं होगा। इस तरह का परिणाम संविधान के मौलिक आदेशों में से एक के खिलाफ होगा, अर्थात् न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना। "

राष्ट्रमंडल पूर्व रिले कैरोल बनाम टेट, 274 ए. 2 डी। 193. वृज मोहन लाल बनाम में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित। भारत संघ, (2012) 6 एस. सी. सी. 502 पैरा 110-111 पर।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. इसके अलावा, न्यायिक अधिकारी लगभग 15 वर्षों से बिना वेतन संशोधन के काम कर रहे हैं। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार वेतन संशोधन की सिफारिश की गई है।

इन कार्यवाही में कम से कम तीन बार। एस. एन. जे. पी. सी. की रिपोर्ट का संज्ञान लेने वाले 28.02.2020 दिनांकित आदेश में, इस न्यायालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि "वही आपत्तियां, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम. संघ का भारत (1993) 4 एस. सी. सी. 288, फिर से उत्तेजित नहीं होगा। न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा कि अन्य योजना और गैर-योजनागत व्यय की तुलना में, उसमें दिए गए निर्देशों के कारण होने वाला वित्तीय बोझ नगण्य है। 12 1 2 तथापि, राज्यों और संघ ने इस न्यायालय के समक्ष अपने शपथपत्रों में इस आपत्ति को उठाया।

28. राज्यों और संघ के हलफनामों को देखने के बाद, इस न्यायालय ने 27.07.2022 पर पाया कि 7 वें केंद्रीय वेतन के विपरीत

ताकि न्यायिक अधिकारियों की पीड़ा को कम किया जा सके। 1 3 न्यायालय ने संघ और राज्य की आपत्तियों पर विचार करने के बाद इसे खारिज कर दिया और एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा अनुशंसित वेतन संरचना के संशोधन को स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट की स्वीकृति से व्यथित होकर संघ ने इस न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की। इस न्यायालय ने दिनांक 05.04.2023 के आदेश द्वारा समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया और पाया कि SNJPC.¹⁴ द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए वित्तीय निहितार्थ को अत्यधिक नहीं माना जा सकता है, फिर भी राज्यों और संघ ने दो बार इसकी स्पष्ट अस्वीकृति के बाद इस आपत्ति को उठाया है। उनकी आपत्ति की अस्वीकृति को भी दोहराया जाता है। न्यायिक अधिकारियों को लंबे समय तक अधर में नहीं छोड़ा जा सकता है। कथित वित्तीय कमी पर वेतन के संशोधन के बिना समय की अवधि

संसाधन।

29. इस न्यायालय ने अपने दिनांकित समीक्षा आदेश 05.04.2023 में समझाया है

निम्नलिखित शब्दों में यह स्थिति:

" 4. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुद्दा यह है कि क्या वृद्धि की मात्रा को कम करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता है

12 पैरा 7 पर WP (C) No.643/2015 में दिनांकित 28.02.2020 आदेश। 13 पैरा 13 पर WP (C) No.643/2015 में दिनांकित 27.07.2022 आदेश। 14 पैरा 19 पर समीक्षा याचिका (डायरी सं.) 34780/2022 में दिनांकित 05.04.2023 आदेश।

एल. एल. इंडिया जज एसोसिएशन V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

पहले दो स्तरों (सिविल जज, जूनियर और सीनियर डिवीजन) में प्रवेश स्तर के आई. ए. एस. अधिकारियों (जूनियर और सीनियर टाइम स्केल) और न्यायिक अधिकारियों के बीच के अंतर को मामूली रूप से कम करने के लिए कम गुणक लागू करने का प्रस्ताव है। इस तरह की कवायद एक से अधिक कारणों से उचित नहीं है। सबसे पहले, प्रारंभिक वेतन ऐसा होना चाहिए जो प्रतिभाशाली युवाओं को न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करे। दूसरा, 2.81 से कम गुणक/कारक के अनुप्रयोग का परिणाम होगा

एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा अपनाए गए सिद्धांत से विचलन में कि न्यायिक अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की सीमा होनी चाहिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि के अनुरूप। इस न्यायालय ने एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिशों को मंजूरी देकर इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। इसलिए, द्वारा लागू सिद्धांत से अलग होने का कोई वैध कारण नहीं है

जे. पी. सी. ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का वेतन संबंधित रैंक के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की तुलना में अधिक होना चाहिए। इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा ए. आई. जे. ए. (2002) में अनुमोदित किया गया है, तीसरा, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (II) V. भारत संघ इस अदालत ने सेवा की तुलना को खारिज कर दिया

न्यायपालिका की प्रशासनिक शर्तों के साथ

कार्यपालक:

“ 7. इसमें जो कहा गया है उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

उसी से निपटने के दौरान समीक्षा के तहत निर्णय

वहाँ विवाद खड़ा हो गया। हालाँकि, हम यह देखने में मदद नहीं कर सकते कि न्यायिक सेवा और अन्य सेवाओं के बीच अंतर को महसूस करने में विफलता समीक्षा याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्णय में दिए गए निर्देशों के प्रति प्रदर्शित शत्रुता के मूल में है। न्यायिक सेवा 'रोजगार' के अर्थ में सेवा नहीं है। न्यायाधीश कर्मचारी नहीं होते हैं। न्यायपालिका के सदस्यों के रूप में, वे राज्य की संप्रभु न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। वे उसी तरह सार्वजनिक पदों के धारक हैं।

मंत्रिपरिषद् के सदस्यों और विधानमंडल के सदस्यों के रूप में। जब यह कहा जाता है कि हमारे जैसे लोकतंत्र में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका राज्य के तीन स्तंभों का गठन करते हैं, तो यह बताने का इरादा है कि राज्य के तीन आवश्यक कार्य राज्य के तीन अंगों को सौंपे गए हैं और उनमें से प्रत्येक राज्य के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जो लोग

राज्य की शक्ति का प्रयोग मंत्री करते हैं, विधायक [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और न्यायाधीश, न कि उनके कर्मचारियों के सदस्य जो करने में सहायता करें। द.

उनके निर्णयों को लागू करने या लागू

मंत्रिपरिषद् या राजनीतिक कार्यपालिका इससे अलग है

सचिवीय कर्मचारी या प्रशासनिक कार्यपालक जो करता है। इसी तरह,

राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों का पालन

विधायक विधायी कर्मचारियों से अलग होते हैं। तो भी।

न्यायिक कर्मचारियों के न्यायाधीश। समानता के बीच है

राजनीतिक कार्यपालिका, विधायक और न्यायाधीश और नहीं

न्यायाधीशों और प्रशासनिक कार्यपालिका के बीच। कुछ में

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लोकतंत्र, कुछ राज्य न्यायपालिकाओं के सदस्य

विधायिका के सदस्यों के रूप में चुना जाता है और

राज्य के प्रमुख। न्यायाधीश, चाहे वे किसी भी स्तर पर हों प्रतिनिधित्व करें, इसके विपरीत

राज्य और उसके अधिकार का

प्रशासनिक कार्यपालक या अन्य सेवाओं के सदस्य।

इसलिए, अन्य सेवाओं के सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

न्यायपालिका के सदस्यों के बराबर, या तो

संवैधानिक या कार्यात्मक रूप से "।

III. जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसका हिस्सा है

बुनियादी संरचना

30. इस न्यायालय ने बार-बार अभिनिर्धारित किया है कि

आई. ए. आर. आई. संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। 1 5 तथापि, न्यायालय की घोषणाएँ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में रही हैं न कि जिला न्यायालय के संदर्भ में। जिला न्यायपालिका कानून को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि दिनांक 05.04.2023 के समीक्षा आदेश में उल्लेख किया गया है:

" 15. जिला अदालतें और अदालतें जो जिले का एक हिस्सा हैं

न्यायपालिका शासन के संरक्षण में एक प्रमुख भूमिका निभाती है

कानून। न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहता है

न्यायपालिका की विश्वसनीयता। जिला न्यायपालिका के पास है
उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका।

जनता का विश्वास पैदा करने और

न्यायाधीशों से अपेक्षित नैतिकता और व्यावसायिकता के मानक
कठोर हैं /

अन्य सेवाओं की तुलना में अधिक

व्यवसाय। पर्याप्त परिलब्धि, पेंशन सुनिश्चित करना और
परिस्थितियाँ

ज़िले के सदस्यों के लिए काम करने की उचित

गुप्ता बनाम। भारत संघ, 1981 पूरक एस. सी. सी. 87; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-डी. एसोसिएशन
पर। वी. भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 441; विशेष संदर्भ सं. 1998 का 1,98 में) 7 एस.
सी. सी. 739; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। वी. भारत संघ,

5 एससीसी 1.

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

न्यायपालिका का दक्षता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है
न्यायिक प्रशासन और प्रभावी निर्वहन

न्यायपालिका को सौंपी गई अनूठी भूमिका "।

जिला न्यायपालिका में स्वतंत्र न्यायाधीश, न्याय, एक प्रारंभिक लक्ष्य 1 6 भ्रमपूर्ण रहेगा। जिला न्यायपालिका, ज्यादातर मामलों में, वह न्यायालय भी है जो वादी के लिए सबसे अधिक सुलभ है। न्यायमित्र उन्होंने कहा कि एक ही दिन में जिला न्यायपालिका ने लगभग 11 लाख 3 हजार मामलों को संभाला। यह देखा गया कि महामारी की अवधि के दौरान भी, जिला न्यायपालिका अभी भी कुशल थी और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए

यह सुनिश्चित करें कि न्याय समय पर दिया जाए। इस प्रकार यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि जिला न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बदले में न्यायपालिका की मूल संरचना का हिस्सा है।

संविधान।

IV. न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है
संविधान के भाग III का कार्यान्वयन

32. संविधान के भाग III की कोई भी व्याख्या

यह आवश्यक है कि मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान एक स्वतंत्र जिला न्यायपालिका द्वारा किया जाए। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हिस्सा है। 1 7 उदाहरण के लिए, अनीता कुशवाहा बनाम। पुशप सूडान [(2016) 8 एस. सी. सी. 509, पैरा 31], इस न्यायालय ने मान्यता दी कि "न्याय तक पहुँच" अनुच्छेद 14 और 21 में निहित है। इस न्यायालय ने कहा:

" 31. यदि "जीवन" का अर्थ न केवल भौतिक अर्थों में जीवन है, बल्कि

अधिकारों का बंडल जो जीवन को जीने लायक बनाता है, कोई न्यायिक नहीं है

या न्याय तक पहुँच से इनकार करने के लिए अन्य आधार

पहुँच लेने के लिए मानव जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेगा

गारंटीकृत जीवन के अधिकार के दायरे से बाहर न्याय के लिए

अनुच्छेद 21 के तहत। इसलिए, हमें धारण करने में कोई संकोच नहीं है

न्याय तक पहुँच वास्तव में जीवन के अधिकार का एक पहलू है

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी। हमें बस जरूरत है

यह जोड़ें कि न्याय तक पहुँच अधिकार का पहलू भी हो सकता है

16 प्रस्तावना इस बात की गारंटी देती है कि "न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक" भारत के सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित होगा।

17 देखिए: हुसैनारा खातून (I) v. गृह सचिव , बिहार राज्य, (1980) 1 एस. सी. सी. 81, पुलिस आयुक्त दिल्ली बनाम। पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय [(1996) 6 एस. सी. सी. 323, पैरा 16]। हुसैन बनाम। सरकार. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का [(2012) 9 एस. सी. सी. 408, पैरा 1।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी जो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

न केवल नागरिकों के लिए बल्कि गैर-नागरिकों के लिए भी।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी न्यायिक तंत्र की अनुपस्थिति या इस तरह के तंत्र की अपर्याप्तता, उन लोगों को रोकने के लिए बाध्य है जो कानूनों के समक्ष समानता के अपने अधिकार को लागू करने और कानूनों के समान संरक्षण की मांग कर रहे हैं।

इस प्रकार कानूनों के समक्ष समानता की गारंटी को नकारता है या

कानूनों का समान संरक्षण और इसे केवल चिढ़ाने तक सीमित करें।

भ्रम "।

33. निष्पक्ष सुनवाई और न्याय तक पहुँच का अधिकार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है, किसी न्यायालय तक भौतिक पहुँच तक सीमित नहीं है। अधिकार में न्यायालय की सभी आवश्यक पूर्वापेक्षाएँ भी शामिल होनी चाहिए, अर्थात्

अवसंरचना, और एक निष्पक्ष, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधीश। दोहराव की कीमत पर, इस देश में अधिकांशवादियों के लिए, एकमात्र

न्याय तक पहुँच के लिए भौतिक रूप से सुलभ संस्थान जिला न्यायपालिका है, जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भी अधिक महत्व रखती है।

34. यह कहने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है कि "न्याय तक पहुँच" और "निष्पक्ष सुनवाई" के अधिकारों का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी निर्णय के नहीं किया जा सकता है।

स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के बिना, मौलिक और संवैधानिक अधिकारों सहित शेष अधिकारों को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से लागू नहीं किया जाएगा। यदि ये साधन अधिकार स्वयं बाधित होते हैं, तो संविधान के भीतर अन्य सभी अधिकार लागू करने योग्य नहीं होंगे।

V. जिला न्यायपालिका के न्यायिक कार्यों की समानता

और उच्च न्यायपालिका

35. जिला न्यायपालिका का आवश्यक कार्य, साथ ही

उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय का कार्य न्याय देना है।
न्यायालय ने अपने समीक्षा आदेश में कहा:

निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से। इस

" 14. चौथा, यह तर्क कि एक समान आई. ओ. आर. जिला अदालतों की तुलना संवैधानिक अदालतों से करेगा, गलत है। ए.

समान गुणक का उपयोग वेतन में समान वृद्धि के लिए किया जाता है न कि अपने आप में समान वेतन के उद्देश्य के लिए। न्यायालयों के पदानुक्रम में सभी न्यायाधीश विवादों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के समान आवश्यक कार्य का निर्वहन करते हैं।

इस प्रकार, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

जब एस. एन. जे. पी. सी. ने गुणक को समान रूप से लागू करने का विकल्प चुना है तो श्रेणीबद्ध आई. ओ. आर. लागू करना उचित नहीं होगा।

36. एक साथ, न्यायालय न्याय प्रशासन के मूल और आवश्यक कार्य के लिए प्रदर्शन करने वाली एकीकृत न्यायिक प्रणाली का गठन करते हैं। वास्तव में रूप और सार दोनों में एकीकृत होने के लिए, जिला न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के बीच वेतन, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों के संदर्भ में एकीकरण होना चाहिए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 125 और 221 के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय वेतन आदि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 के आधार पर पूरे देश में समान है।

37. यह देखते हुए कि एकीकृत न्यायिक प्रणाली के पदानुक्रम में ए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश से ऊपर रखा जाता है, यह इस प्रकार है कि एक जिला न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अधिक वेतन नहीं मिल सकता है। इसलिए, वेतन की अधिकतम सीमा जो एक जिला न्यायाधीश अर्जित कर सकता है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन है जो उपरोक्त कानून के तहत तय किया गया है। एक बार जब जिला न्यायाधीश का वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ निर्धारित किया जाता है, तो यह इस प्रकार होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कोई भी वृद्धि जिला न्यायपालिका में न्यायाधीशों के समान अनुपात में होनी चाहिए। समीक्षा आदेश में, इस न्यायालय ने कहा:

" 16. इस सिद्धांत की वैधता कि न्यायिक अधिकारियों के वेतन में वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की मात्रा पहले भी बढ़ाई जा चुकी है और न्यायिक रूप से तय की गई है। इसलिए, आई. ओ. आर. पर कोई भी आपत्ति इस आधार पर कि इसे कम होना चाहिए

न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि के लिए अपनाया गया

उच्च न्यायालय बिना किसी ठोस आधार के है।

38. संवैधानिक आधारों पर विचार करने के बाद, जिनके आधार पर एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिशों पर विचार किया जाना है, हम

अब वेतन, पेंशन, उपदान आदि के संबंध में सिफारिशों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

5.0 भुगतान पर सिफारिशें

39. हम सबसे पहले वेतन संरचना पर एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिश पर विचार करेंगे। एस. एन. जे. पी. सी. की प्रासंगिक सिफारिशों का सारांश

वेतन को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिफारिशें

सिफारिशें

नहीं।

राज्य/उच्च न्यायालय इन क्षेत्रों में अधिकारियों को फिर से नामित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे।

44.1

एफ. एन. जे. पी. सी. द्वारा अनुशासित अखिल भारतीय पैटर्न के अनुरूप अर्थात् जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है।

44.2

नई वेतन संरचना 'मास्टर पे स्केल' पैटर्न के विपरीत सातवें सी. पी. सी. के मॉडल पर 'वेतन मैट्रिक्स' पैटर्न के अनुसार होगी ताकि विसंगतियों को दूर किया जा सके और वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाया जा सके और स्थापित सिद्धांतों के ढांचे के भीतर सभी संवर्गों के न्यायिक अधिकारियों को उचित लाभ सुनिश्चित किया जा सके। न्यायिक अधिकारियों का वर्गीकरण उनकी स्थिति के आधार पर किया जाएगा

44.3

कार्यात्मक पदानुक्रम रिपोर्ट के पैरा 13.1 के नीचे तालिका-I में क्षैतिज सीमा में परिलक्षित होता है।

44.4 , 44.5

जे-6 और जे-7 को छोड़कर अधिकारी के प्रत्येक पद के लिए प्रारंभिक वेतन प्रत्येक पद के मौजूदा प्रवेश वेतन का लगभग 2.8 गुना है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वृद्धि के समान अनुपात में है। तदनुसार, क्षैतिज सीमा में पहली पंक्ति (जे-1 से जे)

7) उस स्तर पर नई भर्तियों/नियुक्तियों के लिए प्रवेश वेतन को दर्शाता है।

नया औसत वेतन प्रतिशत बनाम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में वेतन

44.6

पी के अनुसार प्रत्येक संवर्ग और श्रेणी के लिए। 182 रिपोर्ट में

वार्षिक वृद्धि @3 प्रतिशत संचयी होगी, जिसका अर्थ है कि

44.7

एफ. एन. जे. पी. सी. और जे. पी. सी. द्वारा अनुशंसित निश्चित राशि वृद्धि के बजाय पिछले वर्ष के मूल वेतन पर 3 प्रतिशत की वृद्धि की गणना की जानी चाहिए।

44.8

पे मैट्रिक्स पैटर्न में अब 44 के बजाय 37 चरण होंगे।

मौजूदा अधिकारियों की नियुक्ति/स्थानांतरण तालिका II में दर्शाया गया है।

44.9

पैरा 13.3, पी. 73

सेवारत न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण/फिटमेंट की प्रक्रिया और

44.10

पदोन्नति पर वेतन निर्धारित करने की प्रक्रिया पैरा 13.5 में बताए अनुसार होगी और

13.8 .

जहां तक वृद्धि की प्राप्ति की तारीख का संबंध है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

44.11 (i)

मौजूदा प्रणाली जिसका विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पालन किया जा रहा है अर्थात वृद्धि

नियुक्ति या पदोन्नति या वित्तीय तिथि के अनुसार वर्ष में एक बार होगा।

उन्नयन।

सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा

44.11 ((ख)

उनकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन। वह वृद्धि केवल पेंशन के उद्देश्यों के लिए होगी और रुपये की ऊर्ध्वाधर सीमा के अधीन होगी। 2,24,100 / - .

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

नए वेतन मैट्रिक्स/वेतन में सभी रैंक/ग्रेड के न्यायिक अधिकारियों का वेतन

44.12

संरचना 01.01.2016 से प्रभावी होगी।
डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2016 के बकाया वेतन का भुगतान कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान किया जाएगा।

44.13

दिनांकित अंतरिम रिपोर्ट के तहत पहले से ही भुगतान की गई अंतरिम राहत को समायोजित करने के बाद

09.03.2018 .

44.14

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर डीए को मंजूरी देने की वर्तमान प्रथा जारी रहेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देश जारी कर सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप संशोधित डीए का लाभ न्यायिक अधिकारियों को बिना किसी देरी के और किसी भी मामले में, केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से 3 महीने के बाद नहीं दिया जाएगा। डीए की संशोधित दरों का लाभ केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में निर्दिष्ट प्रभावी तिथि से प्राप्त होगा।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को प्रथम ए. सी. पी. का अनुदान आवेदन पर आधारित नहीं होगा

44.15 (i)

वरिष्ठता-सह-योग्यता के मौजूदा मानदंड। उत्पादन के संदर्भ में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए नियमों में ढील दी जाएगी। जांच यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए होगी कि क्या कुछ सकारात्मक प्रतिकूल है जैसे कि लगातार खराब/असंतोषजनक प्रदर्शन या गंभीर प्रकृति की प्रतिकूल रिपोर्ट जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकारी इसके लिए अयोग्य है। एसीपी का लाभ।

यदि किसी कारण से ए. सी. पी. के अनुदान में देरी एक वर्ष से अधिक हो जाती है, तो एक अतिरिक्त

44.15 (ख)

प्रत्येक वर्ष की देरी के लिए वृद्धि समायोजन के अधीन दी जाएगी।

ए. सी. पी. के अनुदान पर बकाया राशि निकालना।

जिला न्यायाधीशों (चयन श्रेणी) के पदों को बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया जाएगा।

44.16 (1)

संवर्ग की संख्या मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़कर जिला न्यायाधीशों (सुपर टाइम स्केल) की संख्या संवर्ग की संख्या के मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाएगी। यह 01.01.2020 से प्रभावी होगा।

उन्नयन लाभ जिला न्यायाधीशों को लागू करके दिया जाएगा

44.16 ((ख)

योग्यता और वरिष्ठता के बजाय वरिष्ठता और योग्यता का सिद्धांत।

यदि पद तीन साल तक बना रहता है या बना रहता है तो यह संवर्ग का हिस्सा होगा।

44.16 (iii)

वेतन संशोधन लाभ जो पहले से ही पीठासीन न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध है ताकत।

44.17

जे. पी. सी. की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों (अधीनस्थ न्यायपालिका के नियमित संवर्ग के बाहर) का विस्तार नियमित संवर्ग के न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ उनके लिए भी किया जाएगा।

प्रशासनिक विलंब।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44.18

महाराष्ट्र में परिवार न्यायालयों के न्यायाधीश जो एक अलग संवर्ग से संबंधित हैं, उन्हें नियमित जिला न्यायाधीशों के लिए निर्धारित अनुपात में जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी) और जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) के वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय यदि आवश्यक समझा जाए तो चयन श्रेणी प्रदान करने के लिए न्यूनतम आयु का प्रस्ताव करेगा। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय (पूर्व संवर्ग) को अधिमानतः सामान्य पूल आवास में आवास आवंटित किया जाएगा।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी)/विशेष महानगर मजिस्ट्रेट

44.19

(छोटे आपराधिक मामलों से निपटने के लिए) को 5,000 रुपये प्रति माह के परिवहन भत्ते के अलावा प्रति माह 1,000 रुपये का न्यूनतम पारिश्रमिक मिलेगा और इसे हर पांच साल में उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

5.1 एस. एन. जे. पी. सी. पर इस न्यायालय के आदेश

भुगतान पर सिफारिशें

40. इस न्यायालय ने बाद में तीन विस्तृत आदेश पारित किए हैं।

राज्यों और संघ की आपत्तियों के साथ और उन्हें खारिज कर दिया। पहला आदेश दिनांकित 27.07.2022 है, दूसरा आदेश दिनांकित है

18.01.2023 और अंतिम आदेश दिनांकित 05.04.2023 है। पहले आदेश में, इस न्यायालय ने वेतन संरचना के संशोधन को स्वीकार कर लिया जैसा कि सिफारिश की गई थी एसएनजेपीसी। दिनांक 18.01.2023 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने कुछ राज्यों को दिनांकित 27.07.2022 के आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। इसके बाद, कुछ राज्यों और संघ ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिकाएं दायर कीं। इस न्यायालय ने 05.04.2023 पर समीक्षाओं को खारिज कर दिया। इस प्रकार, वेतन संरचना पर एस. एन. जे. पी. सी. की अधिकांश सिफारिशें अंतिम हो गई हैं।

5.2 अनुशंसाओं पर ध्यान देना

भुगतान करें

41. वेतन पर एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा की गई व्यक्तिगत सिफारिशें हैं -

नीचे विचार किया गया है।

42. जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। द.

इसलिए, न्यायाधीशों के पद पूरे देश में एक समान होने चाहिए। इस संबंध में, एफ. एन. जे. पी. सी. ने निम्नलिखित नामकरण को पूरे भारत में अपनाने का सुझाव दिया-भारत: 18 पैरा 17 पर WP (C) No.643/2015 में दिनांकित 27.07.2022 आदेश। 9 पैरा 19 पर समीक्षा याचिका (डायरी सं.) 34780/2022 में दिनांकित 05.04.2023 आदेश।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

आई. सिविल जज (जूनियर डिवीजन);

ii. सिविल जज (सीनियर डिवीजन);

iii. जिला न्यायाधीश।

43. एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा की गई गहन जांच से पता चला कि ये

कुछ राज्यों में पदनाम नहीं अपनाए गए हैं। आयोग द्वारा कहा गया था कि केरल राज्य अभी भी अपने न्यायाधीशों को मुन्सिफ और 'अधीनस्थ न्यायाधीश' के रूप में नामित करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी यह देखा गया कि पदनाम में कुछ अंतर था। एकरूपता के लिए एक ही छत्र के तहत लाने के लिए इन्हें संशोधित करने की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि इस सिफारिश को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के फैसले के आधार पर एफ. एन. जे. पी. सी. में स्वीकार कर लिया गया था। (II) V. भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 288.20 हम केवल यह दोहरा सकते हैं कि इस निर्देश का पालन उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाए और सभी उच्च न्यायालयों ने अपने पदनामों में संशोधन किया जाए।

एफ. एन. जे. पी. सी. और एस. एन. जे. पी. सी. के सुझावों के अनुरूपता।

44. यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा सुझाए गए वेतन मैट्रिक्स के आलोक में, समान पदनामों के बिना, मुद्दों में उत्पन्न हो सकते हैं

विभिन्न राज्यों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पदनामों के फिटमेंट के लिए भविष्य। इस न्यायालय को ऐसी जटिलताओं से बचना चाहिए।

45. इस प्रकार यह न्यायालय की सिफारिश को स्वीकार करता है

आयोग। नतीजतन, उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि न्यायिक अधिकारियों का पदनाम उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित समान रूप से हो।

II. वेतन मैट्रिक्स मॉडल के अनुसार नई वेतन संरचना

(अनुशंसा 44.2,44.3)

46. एस. एन. जे. पी. सी. ने सिफारिश की है कि वेतन मैट्रिक्स मॉडल,

जिसे 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनाया गया था, न्यायिक अधिकारियों के लिए भी अपनाया जाना चाहिए। यह बांछनीय है क्योंकि यह न्यायाधीशों के लिए वेतन के मामले को सरल बनाता है। विशेष रूप से, यह न्यायालय पहले ही इसे स्वीकार कर चुका है दिनांकित 27.07.2022 आदेश द्वारा सिफारिश। 21 इसकी पुष्टि दिनांक 05.04.2023 के आदेश में की गई है। चूंकि एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिश केवल 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुरूप वेतन संरचना लाने के लिए है, इसलिए इन सिफारिशों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार, यह निर्देश दिया जाता है कि एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा सुझाए गए सुझावों को दर्शाते हुए न्यायिक अधिकारियों की वेतन संरचना को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।

20 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ। (II) v. भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 288 पैरा 19
और 20 पर। 21 पैरा 17 पर WP (C) No.643/2015 में दिनांकित 27.07.2022 आदेश।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

III. 2. 81 का गुणक और इसका समान अनुप्रयोग

(सिफारिशें 44.4-44.6)

47. तर्कसंगतकरण का गुणक/सूचकांक 2.81 रहा है।

एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा न्यायिक अधिकारियों के सभी कैडरों पर लागू करने का सुझाव दिया गया। राज्यों और संघ की आपत्ति यह है कि 7 वें सी. पी. सी. द्वारा अधिकारियों के सभी संवर्गों को 2.81 के आई. ओ. आर. का सुझाव नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि जब केंद्रीय वेतन आयोग ने प्रवेश स्तर के अधिकारियों के लिए 2.57 से लेकर भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए 2.81 तक के स्नातक फिटमेंट कारक को अपनाया, तो न्यायिक अधिकारियों को 2.81 का एक समान गुणक/आई. ओ. आर. नहीं दिया जा सकता था।

48. उनका प्रस्तुत करना गलत है क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्यायिक अधिकारियों के वेतन को उनके वेतन के अनुरूप बढ़ाया जाना है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। जब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को 2.81 का गुणक दिया गया था, तो न्यायिक अधिकारियों को भी वही गुणक दिया जाना था। यह पूर्ववर्ती न्यायिक वेतन आयोगों द्वारा स्थापित और इस न्यायालय द्वारा बार-बार समर्थित उदाहरण रहा है। 22

49. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह कहा जा सकता है कि यह न्यायालय पहले ही राज्यों और संघ की आपत्तियों को खारिज कर चुका है और फलस्वरूप 2.81 के गुणक/युक्तिकरण सूचकांक को स्वीकार किया गया।

आदेश दिनांक 27.07.202223 और आदेश दिनांक 05.04.202324। जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्वीकृति का सैद्धांतिक आधार यह है कि जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों का वेतन केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पर आधारित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका इससे स्वतंत्र है कार्यपालक और इस प्रकार, वेतन सहित सभी पहलू कार्यपालक शाखा के अधिकारियों को दिए गए वेतन पर आधारित नहीं हो सकते हैं।

50. इस प्रकार यह दोहराया जाता है कि एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा सुझाए गए युक्तिकरण के गुणक/सूचकांक को स्वीकार किया जाए। नतीजतन, यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायिक अधिकारियों के वेतन को दिनांकित 27.07.2022 आदेश के साथ संलग्न तालिका-I के अनुसार बढ़ाया जाए।

IV. वृद्धि (अनुशंसा 44.7,44.11)

51. एस. एन. जे. पी. सी. ने मौजूदा में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की।

नियुक्ति की तारीख के अनुसार वर्ष में एक बार वेतन वृद्धि की व्यवस्था

23 पैरा 15-16 पर डब्ल्यू. पी. (सी) No.643/2015 में दिनांकित 27.07.2022 आदेश।
24 पैरा 19 पर समीक्षा याचिका (डायरी सं.) 34780/2022 में दिनांकित 05.04.2023 आदेश।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

या पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन की तिथि। इसमें एकमात्र बदलाव का सुझाव दिया गया था कि न्यायिक अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। आयोग ने

सुझाव दिया कि अतिरिक्त वृद्धि का यह लाभ केवल पेंशन के उद्देश्यों के लिए होगा और रुपये की ऊर्ध्वाधर सीमा के अधीन होगा। 2,24,100 / - . 52. एक सेवानिवृत्त अधिकारी को अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जा सकती है जब वह प्राप्ति की तारीख को सेवा में नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वृद्धि पहले से दी गई सेवा के वर्ष के लिए एक लाभ है। इसलिए, पेंशन की गणना के उद्देश्यों के लिए अंतिम वेतन में शामिल होना चाहिए -

न्यायिक अधिकारी को देय वृद्धि।

53. इस संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णयों के तीन सेट दिए गए थे। मध्य प्रदेश, गुजरात और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया पहला विचार यह है कि जब वेतनवृद्धि सेवानिवृत्ति के अगले दिन देय हो जाती है, तो कर्मचारी को वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। द.

दूसरा विचार, जो मद्रास, उड़ीसा और दिल्ली के उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया था, वह यह है कि वेतनवृद्धि केवल पेंशन के उद्देश्य से अधिकारियों को प्राप्त होगी। तीसरा दृष्टिकोण, आंध्र प्रदेश द्वारा लिया गया,

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान उच्च न्यायालयों का कहना है कि अधिकारियों को वेतनवृद्धि नहीं दी जा सकती है। 54. कानून को अब इस न्यायालय द्वारा हाल के एक फैसले में निपटाया गया है, निदेशक, केपीटीसीएल बनाम। सी. पी. मुंडिनामणि। 25 इस अदालत ने मंजूरी दी

नंद विजय सिंह बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का निर्णय। भारत संघ 2 का आयोजन किया गया था:

" 24. 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिस दिन वेतनवृद्धि देय होती है/देय हो जाती है, उसका महत्व कम हो जाता है और उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवाओं के कारण वेतनवृद्धि प्राप्त करने के सरकारी कर्मचारी के अधिकार को रास्ता देना चाहिए ताकि योजना का इस तरह से अर्थ न लगाया जाए कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित तर्कसंगतता की भावना को आहत करता है।

55. ऐसी परिस्थितियों में, की सिफारिशें

जहां तक यह पेंशन के उद्देश्यों के लिए वृद्धि प्रदान करता है, आयोग पूरी तरह से उचित है। स्वीकृति के परिणामस्वरूप

25 (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 401 पैरा 18 पर।
बनाम। भारत संघ (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन पैरा 24 पर सभी 1090।

26 नंद विजय सिंह

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिफारिश के अनुसार, पेंशन की गणना में पेंशन की गणना के उद्देश्यों के लिए वृद्धि शामिल होनी चाहिए। यह किसी भी भ्रम को भी दूर करेगा। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय लागू नियम में यह कहने के लिए संशोधन करें कि न्यायिक अधिकारी को उनकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन जो वेतन वृद्धि देय होती है, उसे उनकी पेंशन की गणना में उनके अंतिम वेतन के रूप में शामिल किया जा सकता है, जो रुपये की ऊर्ध्वाधर सीमा के अधीन है। 2,24,100 / - .

V. मास्टर पे स्केल से भुगतान के लिए फिटमेंट और माइग्रेशन

मैट्रिक्स प्रणाली (अनुशंसाएँ 44.8, 44.9, 44.10)

56. अदालत ने नोट किया कि आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सूत्र और विधि की सिफारिश की है कि मास्टर वेतन से पलायन

वेतन मैट्रिक्स प्रणाली का पैमाना सहज है। आयोग ने निम्नलिखित फिटमेंट/माइग्रेशन फॉर्मूला तैयार किया है:

" आई. मौजूदा वेतन को 2.81 के कारक से गुणा करें।

ii. अधिकारी पर लागू होने वाले स्तर (यानी जे1, जे2) के संबंध में इस प्रकार का आंकड़ा तालिका-1 में पाया गया है।

iii. जहां सुसंगत स्तर के संबंधित चरण में तालिका-I में एक समान आंकड़ा उपलब्ध है, वहां उस स्तर पर नया संशोधित वेतन तय किया जाएगा।

iv. जहाँ कोई समान आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, वहाँ नए संशोधित वेतन को अगले उच्च चरण में तय किया जाना है।

तालिका में वह स्तर-I "।

57. मामलों को स्पष्ट करने के लिए, आयोग ने चित्रण भी दिए हैं ताकि संबंधित अधिकारियों के लिए फिटमेंट/माइग्रेशन फॉर्मूला को सरल बनाया जा सके। वेतन मैट्रिक्स प्रणाली में स्थानांतरण के नियमों को कूटबद्ध करते समय अधिकारियों द्वारा इन चित्रों पर विचार किया जाना चाहिए। 27 यह ध्यान दिया जा सकता है कि आयोग ने मार्च 2021 में अपनी रिपोर्ट में एक शुद्धिपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें फिटमेंट टेबल से कुछ अंकगणितीय गलतियों को हटा दिया गया है। यह मार्च 2021 की रिपोर्ट के भाग III में परिलक्षित होता है।

58. यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायिक अधिकारियों के वेतन के निर्धारण के लिए एक समान सूत्र और चित्र भी तैयार किए गए हैं जो थे

निम्नलिखित शर्तों में 01.01.2016 पर या उसके बाद पदोन्नत किया गया: 27 पृष्ठ 13.5 पर देखें। 75 - 80 और पैरा 13.8 पी। 81 - 82 रिपोर्ट से।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

“ आई. पदोन्नति की तारीख को तालिका I में स्तर और मूल वेतन की पहचान करें।

ii. एफ. आर.-22 के संदर्भ में उस स्तर में ही एक वृद्धि जोड़ें।

iii. इस प्रकार जो आंकड़ा आया है या जिस स्तर पर एस (उसे) पदोन्नत किया गया है, उसका अगला निकटतम आंकड़ा नया वेतन होगा।

पदोन्नति।

आयोग द्वारा प्रदान किए गए उदाहरण भी पदोन्नति के सूत्र को स्पष्टता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

59. मार्च 2021 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित फिटमेंट/माइग्रेशन के लिए इस सिफारिश को स्वीकार करते समय, यह भी ध्यान दिया जाता है कि उदाहरणों को प्रासंगिक नियमों का हिस्सा बनना चाहिए जिन्हें उच्च न्यायालयों, राज्यों और संघ द्वारा कूटबद्ध किया जाना आवश्यक है। इसलिए, हम सिफारिश को स्वीकार करते हैं और अधिकारियों को आयोग द्वारा दिए गए उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने का निर्देश देते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

VI. 01.01.2016 से सिफारिशों का अनुप्रयोग

(अनुशंसा 44.12)

60. 7 वाँ केंद्रीय वेतन आयोग लागू हुआ

01.01.2016 . हालाँकि, न्यायिक अधिकारियों का अंतिम वेतन संशोधन 01.01.2006 से प्रभावी था। 17 साल से अधिक समय बीत चुका है

न्यायिक अधिकारियों को वेतन संशोधन प्राप्त हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि यह

इस न्यायालय द्वारा पहले से ही अपने दिनांकित 27.07.2022 आदेश में देखा जा चुका है। 28 इसके अलावा, पिछले न्यायिक वेतन आयोगों ने भी संशोधन की सिफारिश की थी

क्रमशः 01.01.1996 और 01.01.2006 से प्रभावी वेतन। इसलिए वेतन के आवेदन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है

01.01.2016 से संरचना। इस प्रकार यह सिफारिश स्वीकार किए जाने के योग्य है। इस प्रकार, यह निर्देश दिया जाता है कि वेतन के संबंध में सिफारिशों के लाभ 01.01.2016 से प्रभावी होने चाहिए।

VII. दिनांकित आदेश में निर्देशों के अनुपालन की स्थिति

27.07.2022 (अनुशंसा सं. 44.13 में संशोधन)

61. जबकि आयोग ने सुझाव दिया कि वेतन का बकाया कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान दिया जाए, इस न्यायालय ने इस पर विचार करने के बाद संघ और राज्य की प्रस्तुतियाँ कि बकाया का भुगतान

28 पैरा 21 पर WP (C) No.643/2015 में दिनांकित 27.07.2022 आदेश।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक बार जाना संभव नहीं हो सकता है और 27.07.2022 दिनांकित आदेश द्वारा निर्देश दिया गया है कि भुगतान तीन अलग-अलग किशतों में किया जाए। इस आदेश के अनुसार

साथ ही, अंतिम किस्त का भुगतान 30.06.2023 द्वारा किया गया था। राज्यों ने पहले ही पहली दो किशतों में भुगतान पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। राज्यों की शिकायतों पर विचार करते हुए, दिनांक 18.01.2023 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया:

" सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने भुगतान किया है

केवल पहली किशत या पहली दो किशतों और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समय बढ़ाने के लिए आवेदन लेकर आए हैं, उन्हें कम से कम इसमें बताए गए समय के भीतर बकाया का भुगतान करने की अनुमति है।

VIII. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर डीए (अनुशंसा 44.14)

62. एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिश है कि महँगाई

बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम इसके कर्मचारी (1969) 2 एस. सी. आर. 113, "जीवन यापन की लागत में वृद्धि के एक हिस्से को बेअसर करने के लिए है। " जब दरें जो केंद्र द्वारा तय की जाती हैं अधिकांश राज्य सरकार का पालन करते हैं, एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिश उचित है। यह सिफारिश देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों की एकरूपता के हित में भी है, जो, जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक प्रमुख सिद्धांत है जिसके आधार पर वर्तमान कार्यवाही आधारित है। विशेष रूप से, महँगाई की एक निश्चित दर

भत्ते से यह भी सुनिश्चित होगा कि न्यायिक अधिकारियों को महँगाई भत्ते के संचय में कोई कमी न आए। 63. पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड और मणिपुर जैसे विभिन्न राज्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के लिए सहमत हैं। द.

पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड और मिजोरम राज्यों ने ऑल इंडिया जज एसोसिएशन V का तर्क दिया है।

भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

कि उनकी दरों को अपनाया जाना चाहिए। अन्य राज्यों ने डी. ए. की दरों के संबंध में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा है। यह देखा गया है कि डीए की एक समान दर एकरूपता के साथ-साथ दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करेगी।

ऐसी परिस्थितियों में, सिफारिश स्वीकार करने योग्य है।

IX. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को प्रथम एसीपी का अनुदान
(अनुशंसा 44.15 (i))

64. आयोग ने सुझाव दिया कि सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) को पहली आश्वस्त कैरियर प्रगति प्रदर्शन के शिथिल मानदंडों के आधार पर दी जानी चाहिए। वर्तमान में, एक सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही पहले एसीपी का हकदार होगा। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) आम तौर पर अपने पहले दो वर्षों में काम सीखने की प्रक्रिया में होता है। प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति से भरे पहले दो वर्षों में अधिकारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन गंभीरता से नहीं किया जा सकता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब पहले दो वर्षों के लिए न्यायिक अधिकारी से कोई वास्तविक कार्य परिणाम की उम्मीद नहीं की जाती है। इसलिए, न्यायिक जीवन के प्रारंभिक चरण के दौरान निपटान के निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में अधिकारी की असमर्थता या मात्रात्मक मानदंडों को पूरा नहीं करने को गंभीरता से देखने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए।

एसीपी के पीछे।

65. एक अन्य पहलू यह है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के संवर्ग में सेवारत न्यायिक अधिकारी। प्रचार के लिए केवल दो रास्ते उपलब्ध हैं

उन्हें, यानी सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और जिला न्यायाधीश। बिना किसी प्रचार के सेवा में ठहराव से मनोबल गिरता है

न्यायिक अधिकारियों के लिए जिनका उनकी स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता है।

66. यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीमित प्रतियोगी परीक्षा जो अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम में इस माननीय न्यायालय के फैसले के आधार पर शुरू की गई है। भारत संघ 2 9 केवल लागू होता है

67. अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में यह न्यायालय। वी. भारत संघ ने केवल दिल्ली उच्च न्यायिक के लिए उपरोक्त शर्तों में ढील दी जहाँ तक यह 10 वर्ष के अनुभव वाले उम्मीदवारों को जिला न्यायाधीश बनने के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति देता है। 3 1 साथ ही, यह देखा गया है कि महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 में पदोन्नति के लिए एक अतिरिक्त विधि की परिकल्पना की गई है।

29 अखिल भारतीय न्यायाधीशों की पीठा वी. भारत संघ (2002) 4 एस. सी. सी. 247 पैरा 28 पर।
30 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ। वी. भारत संघ (2010) 15 एस. सी. सी. 170 (पैरा 7-8)। 3
1 31 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ। वी. भारत संघ (2022) 7 एस. सी. सी. 494।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) को सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नत करने के लिए एक अलग सीमित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके

प्रभाग)। 32 यह ध्यान दिया जा सकता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की भागीदारी के लिए कोई नियम नहीं है। जिला न्यायाधीश के रूप में भर्ती की जाने वाली सीमित प्रतियोगी परीक्षा में।

68. जहां तक पहले ए. सी. पी. के लिए लागू होने वाले नियमों में ढील का संबंध है, यह ध्यान दिया जाता है कि एस. एन. जे. पी. सी. ने सिफारिश की है कि पहले ए. सी. पी. के अनुदान के लिए जांच यह पता लगाने तक सीमित होगी कि क्या कुछ सकारात्मक प्रतिकूल है जैसे कि कोई खराब/असंतोषजनक प्रदर्शन है या गंभीर प्रकृति की प्रतिकूल रिपोर्ट है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकारी पहले ए. सी. पी. का लाभ लेने के लिए अयोग्य है। महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 के नियम 3 (5) में इसी तरह का प्रावधान पहले से मौजूद है। यह नियम निर्धारित करता है कि पहले ए. सी. पी. के लिए आवश्यक ए. सी. आर. मूल्यांकन केवल 'औसत' है और दूसरे ए. सी. पी. के लिए न्यायिक अधिकारी को लगातार पांच वर्षों तक 'अच्छा' मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इस तरह का नियम केवल एक उदाहरण है। उच्च न्यायालय इन शिथिल मानदंडों के लिए अन्य तरीके तैयार कर सकते हैं।

69. इस प्रकार यह निर्देश दिया जाता है कि सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) को प्रथम ए. सी. पी. का अनुदान शिथिल मानदंडों के आधार पर दिया जाए जिन्हें निम्न द्वारा तैयार किया जा सकता है -

आयोग के सुझावों के संदर्भ में उच्च न्यायालय।

ए. सी. पी. के अनुदान में देरी (अनुशंसा 44.15 (ii))

70. आयोग की रिपोर्ट के पैरा 19.4 और 19.5 के अवलोकन से पता चलता है कि कई राज्यों में ए. सी. पी. पैमाने के अनुदान में देरी होती है। द.

आयोग ने पाया कि कुछ क्षेत्राधिकारों में, पूरा होने के बाद भी 10 साल से अधिक की सेवा, सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) को एसीपी प्रदान नहीं किया गया था। यह अक्षम्य है। प्रशासनिक देरी के कारण न्यायिक अधिकारियों के करियर में ठहराव से मनोबल गिरता है

और अपने करियर के महत्वपूर्ण चरणों में उत्साह, जहां वे कैरियर की प्रगति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं।

71. एस. एन. जे. पी. सी. का यह निष्कर्ष कि ए. सी. आर. की समय पर तैयारी और जांच की कमी देरी का प्राथमिक कारण है, चिंताजनक है। ए. सी. आर. एस. को समय पर और बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए ताकि

यह सुनिश्चित करें कि पूरी न्यायिक प्रणाली कुशलता से काम कर रही है। तदनुसार, उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा सकता है कि भविष्य में एसीआर बनाने में देरी से बचा जाए।

32 नियम 5, महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008।

72. अलग से, भविष्य में इस देरी से बचने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि एसीपी के अनुदान की प्रक्रिया 3 महीने के लिए शुरू की जानी चाहिए जिस तारीख को न्यायिक अधिकारी 5/10 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, उससे पहले न्यायिक अधिकारी को वित्तीय लाभों का भुगतान न्यायिक अधिकारी द्वारा सेवा के 6 वें/11 वें वर्ष में कदम रखने के बाद 6 महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि यदि ए. सी. पी. के अनुदान में हर वर्ष देरी होती है, तो ए. सी. पी. के साथ समायोजन के अधीन देरी के हर वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वृद्धि दी जाएगी।

बकाया राशि।

73. आयोग की सिफारिशें उचित हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रशासनिक पक्ष पर देरी से बचा जाना चाहिए जो एक न्यायिक अधिकारी के करियर को स्थिर करने का प्रभाव डालती है। द.

आयोग के सुझावों से ए. सी. पी. को समय पर अनुदान देने के लिए बहुत आवश्यक दक्षता और शायद एक मानक संचालन प्रक्रिया आएगी। इस प्रकार, सिफारिश स्वीकार किए जाने के योग्य है।

XI. जिला न्यायाधीशों के प्रतिशत में परिवर्तन (चयन)

ग्रेड) और जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल)

(अनुशंसा 44.16)

74. आयोग ने प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की है।

जिला न्यायाधीश जो जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी) और जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) के हकदार होंगे। आयोग का तर्क है कि जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) और जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) के सीमित प्रतिशत के कारण, बड़े राज्यों के कई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पदों तक पहुंचने में असमर्थ हैं, भले ही उन्होंने जिला न्यायाधीश संवर्ग में काफी समय बिताया हो। इसने यह भी पाया कि अक्टूबर, 2019 तक 7382 जिला न्यायाधीशों की संवर्ग संख्या में से केवल 1515 न्यायाधीशों को चयन श्रेणी और सुपर टाइम स्केल का लाभ मिल रहा था।

75. सुपर टाइम स्केल और चयन ग्रेड के लाभ उनकी सेवानिवृत्ति से पहले अधिकांश जिला न्यायाधीशों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

इससे बचना चाहिए। आयोग की यह सिफारिश कि चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल पदों में क्रमशः 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, स्वीकृति के योग्य है। अनिवार्य रूप से, यह आवश्यक होगा कि प्रवेश स्तर पर जिला न्यायाधीश 50 प्रतिशत, चयन ग्रेड 35 प्रतिशत और सुपर टाइम स्केल-जिले की कुल संवर्ग संख्या का 15 प्रतिशत होगा। न्यायाधीश।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

76. अनुशंसाएँ 44.16 (ii) और (iii) निम्नलिखित सिद्धांत को लागू करके जिला न्यायाधीशों को दिए जाने वाले उन्नयन के संबंध में हैं -

वरिष्ठता-सह-योग्यता और इसके अलावा यदि पद तीन साल तक बना रहता है या बना रहता है तो यह संवर्ग संख्या का हिस्सा होगा। एस. एन. जे. पी. सी. की इन सिफारिशों पर उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वे नहीं करती हैं।

वेतन के मुद्दों पर असर पड़ता है, जिन पर इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

बारहवीं। पीठासीन न्यायाधीशों को वेतन संशोधन दिया जाएगा

औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय (अनुशंसा)

44.19)

77. यद्यपि श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत बनाए गए दोनों वैधानिक न्यायालयों की अध्यक्षता न्यायिक अधिकारी नहीं करते हैं, वे समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर जिला न्यायाधीशों के रूप में समान वेतन के हकदार हैं। इस सिद्धांत का पालन करते हुए, केरल राज्य बनाम में यह न्यायालय। बी. रंजीत कुमार 3 4 और राज्य

महाराष्ट्र बनाम. लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन 3 5 ने अभिनिर्धारित किया कि श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक अधिकारियों के बराबर माना जाना चाहिए। न्यायाधिकरण की सिफारिश कि वेतन संशोधन को औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों के न्यायाधीशों तक बढ़ाया जाए, इस प्रकार स्वीकृति के योग्य है क्योंकि यह केवल निर्धारित कानून का विस्तार है।

इस न्यायालय द्वारा नीचे।

तेरहवीं। महाराष्ट्र में पारिवारिक न्यायालयों में न्यायाधीश

(अनुशंसा 44.18)

78. आयोग ने देखा कि परिवार न्यायालयों में न्यायाधीश

महाराष्ट्र में एक अलग प्रक्रिया और अधिकारियों के माध्यम से भर्ती की जाती है।

एक अलग संवर्ग का हिस्सा बनें। साथ ही, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों (भर्ती और सेवा शर्तें) महाराष्ट्र नियम, 1990 के नियम 8 में यह भी प्रावधान है कि न्यायाधीश नगर सिविल न्यायालय, बॉम्बे के न्यायाधीशों (क्रमशः प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीश) के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और अन्य स्थानों पर जिला न्यायाधीश को स्वीकार्य वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा।

79. आयोग की सिफारिश है कि -

परिवार न्यायालय भी चयन श्रेणी के लाभ का हकदार होगा और

33 औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1947 की धारा 7 और 7 ए क्रमशः।

34 केरल राज्य बनाम। बी. रंजीत कुमार, (2008) 12 एस. सी. सी. 219 पैरा 19 पर। 35 महाराष्ट्र राज्य बनाम। लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन , (1998) 2 पैरा 20 पर एस. सी. सी. 688।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

सुपर टाइम स्केल भी। आयोग ने आगे सिफारिश की है कि भी दिए जाएँ।

आवास के सामान्य पूल से उन्हें आवास

80. एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिश उसी के अनुरूप है

केरल राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित ऊपर उल्लिखित सिद्धांत। बी. रंजीत कुमार 3,6 और महाराष्ट्र राज्य बनाम लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन 3 7 श्रम न्यायालयों के लिए। जब न्यायिक अधिकारियों द्वारा समान काम किया जाता है, तो उनका वेतन और सेवा की शर्तें भी समान होनी चाहिए। अतः आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है।

XIV। विशेष न्यायपालिका को न्यूनतम पारिश्रमिक

मजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी) और विशेष महानगर

मजिस्ट्रेट (अनुशंसा 44.19)

81. आयोग की रिपोर्ट के पैरा 36 को पढ़ने से पता चलता है कि

पारिश्रमिक और इसके परिणामस्वरूप न्यूनतम वेतन की सिफारिश की गई है रु. 30,000 प्रति माह और रुपये का परिवहन भत्ता। 5,000 / - . आयोग ने आगे सिफारिश की है कि यह लाभ 01.04.2019 से दिया जाएगा।

82. न्यायमित्र ने तर्क दिया है कि रु। 30,000 अपर्याप्त है

आज और इतनी कम राशि न्यूनतम मजदूरी को पूरा नहीं कर सकती है।

कुछ राज्यों में आवश्यकताएँ। यह देखते हुए कि धारा 261, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसे अपराधों का मुकदमा चला सकते हैं जो जुर्माने या 6 महीने से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं, ऐसे मजिस्ट्रेटों को न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले के रूप में नहीं माना जा सकता है जो नियमित मजिस्ट्रेटों के लिए अतुलनीय हैं। इस प्रकार, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता न्यायिक स्वतंत्रता का उतना ही हिस्सा है जितना कि नियमित मजिस्ट्रेटों के लिए है। इस प्रकार, आयोग की सिफारिशों को संशोधित करते हुए पारिश्रमिक रुपये निर्धारित किया गया। 45,000 / - प्रति माह और रुपये की अतिरिक्त राशि। 5,000 / - परिवहन भत्ता के रूप में।

83. सुविधा के उद्देश्य से, सिफारिशें और

उनके संशोधन/स्वीकृति को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

36 केरल राज्य बनाम। बी. रंजीत कुमार, (2008) 12 एस. सी. सी. 219 पैरा 19 पर। 37 महाराष्ट्र राज्य बनाम। लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन , (1998) 2 पैरा 20 पर एस. सी. सी. 688।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिफारिशें

अनुशंसा सं।

इ

सका आदेश

अदालत

राज्य/उच्च न्यायालय तत्काल कार्रवाई करेंगे।

स्वीका

र किया गया।

44.1

अधिकारियों को फिर से नामित करने के लिए कदम

अखिल भारतीय स्वरूप के अनुरूपता

एफ. एन. जे. पी. सी. द्वारा यथा अनुशंसित

जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है।

44.2

' VII के मॉडल पर 'पे मैट्रिक्स' पैटर्न

मास्टर वेतनमान के विपरीत सी. पी. सी. '

वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाना और यह सुनिश्चित करना कि सभी न्यायिक अधिकारियों को उचित लाभ

स्थापित ढांचे के भीतर कैडर

सिद्धांत

स्वीकृत न्यायिक अधिकारियों का वर्गीकरण

44.3

में उनकी स्थिति के आधार पर होगा

क्षैतिज में प्रतिबिंबित कार्यात्मक पदानुक्रम

तालिका में सीमा-1 के पैरा 13.1 से नीचे

रिपोर्ट करें।

अधिकारी के प्रत्येक पद के लिए प्रारंभिक वेतन स्वीकार किया जाता है।

44.4 , 44.5

के मौजूदा प्रवेश वेतन का लगभग 2.8 गुना

जे-6 और जे-7 को छोड़कर प्रत्येक श्रेणी, जो

वृद्धि का समान अनुपात

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तदनुसार, पहली पंक्ति

क्षैतिज सीमा में (जे-1 से जे-7) दर्शाता है

नई भर्तियों/नियुक्तियों के लिए प्रवेश वेतन

उस स्तर पर।

स्वीका

र किया गया।

नया औसत वेतन प्रतिशत बनाम-ए-विज़

44.6

संबंध में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन

पी के अनुसार प्रत्येक संवर्ग और श्रेणी के लिए। 182 में से

रिपोर्ट करें।

वार्षिक वृद्धि @3 प्रतिशत स्वीकार की जाएगी।

44.7

संचयी, जिसका अर्थ है कि

3 प्रतिशत की वृद्धि की गणना इस पर की जानी है

पिछले वर्ष का निश्चित वेतन के बजाय मूल वेतन

द्वारा अनुशंसित राशि वृद्धि

एफएनजेपीसी और जेपीसी।

स्वीका

र किया गया।

44.8

वेतन मैट्रिक्स पैटर्न में, होगा

अब 44 के बजाय 37 चरण

44.9

मौजूदा का फिटमेंट/प्रवास

स्वीका

र किया गया।

होना।

-

अधिकारी तालिका II में दर्शाए गए अनुसार होंगे -

के

साथ पढ़ें

पैरा 13.3, पी. 73

शुद्धिप

त्र दिनांकित

मार्च

2021

द्वारा

प्रस्तुत किया गया

एस. एन. जे. पी. सी. ऑल इंडिया जज एसोसिएशन V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

सेवा करने वाले के स्थानांतरण/फिटमेंट की प्रक्रिया-से

44.10

न्यायिक अधिकारी और नियत करने की प्रक्रिया भी।

पदोन्नति पर वेतन पैरा में बताए अनुसार होगा।

करण

शुद्धि

कित मार्च

दिनां

13.5 और 13.8।

21 प्रस्तुत किया गया

20

नजेपीसी द्वारा

एसए

कार किया गया।

स्वी

जहां तक वृद्धि की प्राप्ति की तारीख का संबंध है, वहाँ

44.11 (1)

मौजूदा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा जो

विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पालन किया जा रहा है अर्थात्

वृद्धि वर्ष में एक बार की तारीख के अनुसार होगी

नियुक्ति या पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन।

सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को लाभ स्वीकार किया जाएगा।

44.11 ((ख)

अगले दिन देय होने वाली वृद्धि

उनकी सेवानिवृत्ति। यह वृद्धि इसके लिए होगी

केवल पेंशन के उद्देश्य और इसके अधीन होंगे

रुपये की ऊर्ध्वाधर छत। 2,24,100 / - .

न्यायिक अधिकारियों का वेतन

स्वी

कार किया गया।

44.12

सब कुछ

रैंक/ग्रेड

नए वेतन में

मैट्रिक्स/वेतन संरचना होगी

01.01.2016 से प्रभावी

डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2016 का बकाया भुगतान स्वीकार किया जाएगा।

44.13

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान, समायोजन के बाद
अंतरिम के तहत पहले से ही भुगतान की गई अंतरिम राहत

रिपोर्ट दिनांकित 09.03.2018।

स्वीकृत दरों पर डीए को मंजूरी देने की वर्तमान प्रथा

44.14

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित

समय चलता रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय
निर्देश जारी कर सकते हैं कि संशोधित डीए का लाभ

केंद्र द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप
सरकार को समय-समय पर भुगतान किया जाएगा

न्यायिक अधिकारी बिना किसी देरी के, और किसी भी मामले में, नहीं
जारी होने की तारीख से 3 महीने बाद

केंद्र सरकार का आदेश। इसका लाभ

डीए की संशोधित दरें इससे प्राप्त होंगी

द्वारा जारी आदेश में निर्दिष्ट प्रभावी तिथि

इस दिशा में केंद्र सरकार।

23]

44.15 (i)

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को प्रथम ए. सी. पी. का अनुदान करेंगे।

स्वीकार

किया,

मौजूदा के आवेदन पर आधारित नहीं होना

मानक

होने चाहिए

वरिष्ठता-सह-योग्यता का मानक। वहाँ होगा

उच्च द्वारा

प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए नियमों में ढील

के

अनुसार

फैसला

उत्पादन की शर्तें। जांच इसके लिए होगी

यह पता लगाने का सीमित उद्देश्य है कि क्या

कुछ भी सकारात्मक रूप से प्रतिकूल जैसे कि लगातार

खराब/असंतोषजनक प्रदर्शन या प्रतिकूल

कि अधिकारी लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य है

एसीपी।

44.15 (ख)

यदि किसी कारण से ए. सी. पी. के अनुदान में देरी स्वीकार की जाती है

एक वर्ष से अधिक के लिए एक अतिरिक्त वृद्धि

प्रत्येक वर्ष विलंब की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि -
अनुदान पर बकाया राशि निकालते समय समायोजन

एसीपी।

44.16 (i)

जिला न्यायाधीशों (चयन श्रेणी) के पद स्वीकार किए गए

संवर्ग की संख्या को बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया जाएगा।
मौजूदा 25 प्रतिशत की तुलना में, और जिला

न्यायाधीशों (सुपर टाइम स्केल) को बढ़ाया जाएगा

15 % कैडर की ताकत की तुलना में

मौजूदा 10 प्रतिशत। यह प्रभावी होगा

01.01.2020

कॉन

होना

उन्नयन का लाभ दिया जाएगा

44.16 ((ख)

जिला न्यायाधीशों के सिद्धांत को लागू करके

द रिलेवन

वरिष्ठता।

यदि पद तीन साल तक बना रहता है या बना रहता है

विपक्ष

होना

44.16 (iii)

यह कैडर की ताकत का हिस्सा होगा।

द रिलेवन

वेतन संशोधन लाभ जो पहले से ही है

स्वीकार

किया गया।

44.17

वे भी न्यायिक अधिकारियों के साथ
प्रशासनिक विलम्ब के बिना नियमित संवर्ग।

44.18

स्वीकार किए गए पारिवारिक न्यायालयों के न्यायाधीश
महाराष्ट्र जो एक अलग संवर्ग से संबंधित है

जिले के वेतन का लाभ बढ़ाया जाए
न्यायाधीश (चयन श्रेणी) और जिला न्यायाधीश

(सुपर टाइम स्केल) समान अनुपात में

नियमित जिला न्यायाधीशों के लिए विहित। द हाई
न्यायालय अनुदान के लिए न्यूनतम आयु का प्रस्ताव करेगा

यदि आवश्यक समझा जाए तो चयन श्रेणी। द.

अधिमानत: आवंटित क्वार्टर, सामान्य पूल में
आवास।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय)

विशेष।

44.19

स्वीकार
किया गया।

बदलाव

वर्ग)/विशेष महानगर मजिस्ट्रेट (कार्य करने वाले)
छोटे आपराधिक मामलों के साथ) न्यूनतम मिलेगा

रु.

45,000

प्रति माह Rs.30,000/- का पारिश्रमिक

और रु.

5,0

5, 000/- रुपये के परिवहन भत्ते के अतिरिक्त

महीने के
लिए

प्रति माह डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2019 और
हर पाँच साल में उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

6. सम्मान, कृतज्ञता पर सिफारिशें

और सेवानिवृत्ति की आयु ई. टी. सी.

84. अब हम एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिशों पर विचार करेंगे।

पेंशन, ग्रेच्युटी आदि। सुविधा के उद्देश्यों के लिए, सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

सिफारिशें

सिफारिशें

नहीं।

01.01.2016-पेंशन/परिवार के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए पेंशन में कोई बदलाव नहीं

39.1

पेंशन सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत होगी।
सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की संशोधित पेंशन अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

39.2

पेंशन संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए रिपोर्ट में दिए गए सूत्रीकरण:
(i) गुणक कारक

39.3

पेंशन के लिए लागू होने वाले 2.81 का; या (ii) पेंशनभोगियों को फिटमेंट टेबल में उचित रूप से फिट किया जाना (तालिका II, पैरा 13.3, Ch. II, खंड। आई, पी। 73) जो भी अधिक हो
न्यायिक अधिकारी जो 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें वैचारिक रूप से रखा जाएगा

39.4

संबंधित चरण।

न्यायिक अधिकारियों के लिए जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, यदि कोई परिणामी नहीं है

39.5

इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के आधार पर संबंधित सरकार द्वारा निर्धारण किया गया है, उक्त लाभ पहले उन्हें आगे दिए बिना दिया जाएगा।

विलम्ब।

बार में अभ्यास के वर्षों की संख्या के लाभ अधिकतम के अधीन

39.6

एच. जे. एस. की सीधी भर्तियों को दस साल का महत्व दिया जाएगा जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

01.01.2016 .

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए परिवार के मौजूदा प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया गया है।

4.1

पेंशन, अर्थात् यह सेवानिवृत्ति के समय अंतिम रूप से प्राप्त वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

न्यायिक अधिकारी

परिवार के पात्र सदस्यों को 30 प्रतिशत की दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा जैसा कि नियम में दिया गया है।

4.2

54 सी. सी. एस. (पेंशन) नियम 1972 जीवनसाथी की मृत्यु के बाद पति या पत्नी के बराबर है।

4.3

पारिवारिक पेंशन की मात्रा का निर्धारण उसी तरह किया जाएगा जैसे पेंशन की मात्रा का निर्धारण किया जाता है।

आश्रित परिवार के संबंध में किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आय सीमा, यदि कोई हो

4.4

पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए सदस्य (जीवनसाथी के अलावा) प्रति माह (तीस हजार रुपये प्रति माह) से कम नहीं होंगे।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा

आयु पूरी होने पर और दरों पर पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा

21.1

पी में तालिका के अनुसार निर्दिष्ट 49 , खण्ड. द्वितीय भाग-I
अतिरिक्त पेंशन का यह लाभ सभी पात्र लोगों को मिलेगा।

21.2

पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2016
जिन लोगों ने लाभ उठाया है, उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी।

21.3

कुछ राज्य सरकारों के मौजूदा आदेशों के अनुसार 65 या 70 वर्ष की आयु
पूरी होने पर अतिरिक्त पेंशन

21.4

राज्य सरकारें सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को भी 75 वर्ष की आयु तक
प्रचलित लाभ जारी रखने का विकल्प चुन सकती हैं।

ग्रेच्युटी

सेवानिवृत्ति उपदान की गणना सी. सी. एस. (पेंशन) के नियम 50 (1) (ए)
के अनुसार की जाएगी।

8.1

नियम 1972।

सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान के लिए अधिकतम सीमा रु. 20 लाखों

8.2

जब भी डीए में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो इसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि
की जाएगी।

ये सिफारिशें 01.01.2016 से प्रभावी होंगी।

8.3

उन अधिकारियों को जो 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान किया है

8.4

पूर्व-संशोधित वेतन और उस समय की अधिकतम सीमा के अनुसार, वेतन के संशोधन के कारण देय अंतर उपदान का भुगतान संशोधित प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

अधिकतम सीमा।

मृत्यु उपदान का भुगतान पी में तालिका के अनुसार किया जाएगा। 52 , खण्ड. II लंबाई के आधार पर

8.5

सेवा में

न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु में कोई बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है।

मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता

सी. सी. एस. (पेंशन) नियमों के नियम 54 (3) के अनुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ,

9.1

दिनांकित अधिसूचना 19.09.2019 के माध्यम से संशोधित परिवार तक विस्तारित किया जाएगा।

सदस्य।

अन्य लाभ जैसे एकमुश्त अनुदान, अनुकंपा नियुक्ति,

9.2

राज्यों में पहले से लागू सरकारी आवासों आदि में रहने की अनुमति

मृत्यु उपदान के अलावा आवेदन करना जारी रखें।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को सहायता

उन्हें उचित सहायता प्रदान करके विशेष ध्यान दिया जाएगा।

11.1

पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के चिकित्सा बिलों को संसाधित करना जो बहुत बड़े, कमजोर या अलग तरह से सक्षम हैं या गंभीर बीमारी के लिए रोगी उपचार से गुजर रहे हैं। जिला न्यायाधीश, यदि आवश्यक हो तो, लिसोनिंग कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे।

11.2

अस्पताल में भर्ती की सुविधा और चिकित्सा बिल प्राप्त करने में आपात स्थिति

पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को तुरंत मंजूरी दे दी गई। विशेष प्रकोष्ठ को अभ्यावेदनों को संसाधित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है

11.3

पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए और कार्रवाई शुरू करने के लिए जिस पर विचार किया जा सकता है शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए उपयुक्त, उच्च में बनाया जाएगा

उच्च न्यायालय में संयुक्त पंजीयक के पद के अधिकारी की देखरेख में न्यायालय

अदालत।

उच्च न्यायालय के कार्यकरण की देखरेख के लिए एक न्यायाधीश नामित किया जाएगा

11.4

विशेष प्रकोष्ठ और आवश्यक निर्देश जारी करें।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश संघों के प्रतिनिधियों को मिलने की अनुमति होगी।

11.5

उच्च न्यायालय के महापंजीयक वर्ष में कम से कम एक बार इस पर चर्चा करने के लिए

समस्याएँ, यदि कोई हों।

11.6

पेंशनभोगियों और परिवार के आंकड़ों को संकलित करने के लिए उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री

पेंशनभोगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन. पी. एस.)/परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना

31.1

यह सभी न्यायिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

परिभाषित लाभ पेंशन योजना/पुरानी पेंशन योजना इन पर लागू होगी -

31.2

न्यायिक सेवा में शामिल होने की तारीख चाहे जो भी हो, सभी न्यायिक अधिकारी।

31.3

उन लोगों के लिए जिनके पास 01.01.2004 के बाद न्यायिक सेवा है, योगदान एक साथ
उन पर अर्जित रिटर्न के साथ उन्हें वापस कर दिया जाएगा या उन्हें हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

जीपीसी खाता।

31.4

सरकार न्यायिक सेवा में नए प्रवेशकों के जी. पी. एफ. खाते को 01.01.2004 के बाद खोलने की सुविधा प्रदान करेगी और उनके योगदान को इसके साथ हस्तांतरित करेगी।

उस पर अर्जित प्रतिफल।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. अनुशंसाओं पर विचार

पेंशन, ग्रेजुटी ई. टी. सी.

85. पेंशन पर एस. एन. जे. पी. सी. द्वारा की गई व्यक्तिगत सिफारिशों पर नीचे विचार किया गया है।

I. सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन के प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं 01.01.2016 पर या उसके बाद (अनुशंसा 39.1)

86. आयोग ने किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है

पेंशन का वर्तमान प्रतिशत, पेंशन के लिए अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत और पारिवारिक पेंशन के लिए अंतिम वेतन के लिए 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। एफ. एन. जे. पी. सी. ने भी इस स्थिति की सिफारिश की थी और इस न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया था। इसलिए, जब किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की जाती है, तो सिफारिश के संबंध में कोई वास्तविक आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है।

II. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की संशोधित पेंशन होनी चाहिए

50 % अंतिम आहरण वेतन

87. एफ. एन. जे. पी. सी. और एक व्यक्ति आयोग की राय पर विचार करने के बाद, आयोग ने सिफारिश की कि न्यायिक आई. डी. 1 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की संशोधित पेंशन सेवानिवृत्ति के समय पद के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होनी चाहिए। यह भी इसके निर्माण में अपरिवर्तित है और इस प्रकार बही रहता है।

III. वेतन मैट्रिक्स में पेंशनभोगियों का गुणक और फिटमेंट

(अनुशंसा सं. 39.3,39.4)

88. वेतन पर एस. एन. जे. पी. सी. की सिफारिशों के परिणामस्वरूप पेंशनभोगियों को भी समान रूप से लाभ होगा। की सिफारिश

कमीशन यह है कि 2.81 का गुणक पेंशनभोगियों पर भी समान रूप से लागू होगा। इसके परिणामस्वरूप पेंशनभोगियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

इस आधार पर उन्हें टेबल और पेंशन का भुगतान किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, न्यायिक अधिकारियों के बीच पेंशन की समानता सुनिश्चित करने के लिए जो

समान स्तर पर लेकिन विभिन्न वेतनमानों के तहत, पेंशन को समान स्तर पर लाया जाना चाहिए। व्यापक विश्लेषण के बाद, आयोग ने अपनी सिफारिशों को स्पष्ट करने के लिए कुछ चित्र भी शामिल किए हैं। चित्र सिफारिश को स्पष्टता प्रदान करते हैं और इसलिए सिफारिश के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

89. यह ध्यान दिया जा सकता है कि वेतन में फिटमेंट पर सिफारिश के साथ, एस. एन. जे. पी. सी. ने अपने पूरक में फिटमेंट पर एक शुद्धिपत्र जारी किया है मार्च 2021 की रिपोर्ट। यह शुद्धिपत्र मूल रिपोर्ट में की गई अंकगणितीय गलतियों को ठीक करता है। इसलिए, फिटमेंट टेबल को फिटमेंट पर सही किए गए टेबल के अनुसार समझा जाना चाहिए।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

90. आयोग की सिफारिशों में योग्यता है।

वेतन का संशोधन पेंशन के संशोधन में भी दिखाई देना चाहिए। इसलिए, जो गुणक वेतन पर लागू होता है, वह पेंशन पर भी लागू होना चाहिए।

नतीजतन, पेंशनभोगियों को वेतन मैट्रिक्स में उसी योजना में फिट किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह सिफारिश स्वीकार की जाती है।

IV. न्यायिक अधिकारियों का परिणामी पुनर्निर्धारण जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त (अनुशंसा सं. 39. 5)

91. आयोग ने नोट किया कि रिपोर्ट में विसंगति के कारण

एक व्यक्ति आयोग के अनुसार, 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को समान रूप से नहीं दी जा रही थी। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में यह न्यायालय वी. भारत संघ, (2014) 14 एस. सी. सी. 444 (दिनांक 08.10.2012) को एक-व्यक्ति आयोग द्वारा की गई त्रुटि से अवगत कराया गया और इसे ठीक करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, आवेदन में प्रार्थना डाक तक सीमित थी 2006 सेवानिवृत्त। मुकदमेबाजी के दूसरे 3-8 और तीसरे दौर 3-9 में, सर्वोच्च न्यायालय ने

न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने दिनांक 1 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया और 1996 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए पेंशन में संशोधन का निर्देश दिया। पर्याप्त सावधानी बरतते हुए आयोग ने सिफारिश की कि जिन राज्यों ने 1996 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को यह लाभ नहीं दिया है, उन्हें भी यही लाभ दिया जाना चाहिए।

92. आयोग की सिफारिश केवल आगे बढ़ाने के लिए है

समानता। राज्य सरकारों को पहले भी परिणामी पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, यदि इस तरह के परिणामी पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है, तो वे अधिकारी जो 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, और जिनकी उम्र काफी अधिक होगी, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। ऐसी स्थिति से बचा जाना चाहिए और इसलिए सिफारिश स्वीकार किए जाने योग्य है। यह न्यायालय इस सिफारिश का निर्देश देता है कि

तुरंत और बिना किसी देरी के लागू किया गया।

V. गणना करते समय बार में वर्षों के अभ्यास का लाभ पेंशन (अनुशंसा सं. 39. 6)

93. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार करने के बाद

एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम अखिल भारतीय युवा वकील संघ (2009) 14 एस. सी. सी. 49, आयोग ने सिफारिश की कि

38 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में दिनांकित 14.07.2016 आदेश। वी. डब्ल्यू. पी. (सी) No.1022/1989 में भारत संघ।
39 अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में दिनांकित 13.03.2018 आदेश। वी. डब्ल्यू. पी. (सी) No.1022/1989 में भारत संघ।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करते समय अधिकतम 10 वर्ष के वेटेज के अधीन बार में अभ्यास के वर्षों को दिया जाएगा। एन. सी. टी. दिल्ली सरकार के इस न्यायालय ने तर्क दिया कि इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि अन्यथा बार से सीधी भर्ती जो जिला न्यायाधीश बन जाता है, वह पूर्ण पेंशन का हकदार नहीं होगा। यह सिफारिश, इस न्यायालय के फैसले का कार्यान्वयन होने के कारण, स्वीकृति के योग्य है। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

VI. पारिवारिक पेंशन पर सिफारिशें (अनुशंसा संख्या। 4. 1 से 4.4)

94. जहाँ तक पारिवारिक पेंशन का संबंध है, आयोग ने नहीं किया है

मौजूदा प्रतिशत में किसी भी बदलाव की सिफारिश की जाती है, यानी अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत। इसलिए, यह सिफारिश, इस प्रकार, किसी भी आगे के विचार-विमर्श की गारंटी नहीं देती है क्योंकि यह केवल

मौजूदा व्यवस्था। सिफारिश स्वीकार की जाती है।

95. साथ ही आयोग ने मृत्यु के बाद परिवार के पात्र सदस्य को 30 प्रतिशत की दर से पारिवारिक पेंशन देने की सिफारिश की है।

(पेंशन) नियम, 1972, जो केंद्रीय सिविल सेवाओं के सदस्यों को समान लाभ प्रदान करता है। इस प्रकार यह सिफारिश भी स्वीकार की जाती है क्योंकि यह केंद्रीय सिविल सेवाओं के सदस्यों को दी गई है।

96. जाहिर है, पारिवारिक पेंशन की मात्रा को उसी गुणक/तर्कसंगतकरण सूचकांक के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए जो पेंशन के लिए लागू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वही कारक जो वेतन और पेंशन पर लागू होते हैं।

उनकी वृद्धि के कारण पारिवारिक पेंशन पर भी समान रूप से लागू होता है। आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है। हम स्वीकार करते हैं कि

सिफारिश करें और निर्देश दें कि पारिवारिक पेंशन की मात्रा भी उसी तरह तय की जाए जैसे पेंशन की मात्रा तय की जाती है।

97. अंतिम सिफारिश यह है कि निर्धारित आय सीमा पर

राज्यों द्वारा पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होना। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा रु। 30,000 / - . यह सीमा उचित है लेकिन यह राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे एक उच्च सीमा निर्धारित करें जो न्यायिक अधिकारियों के लिए अधिक फायदेमंद हो। इस प्रकार, सिफारिश स्वीकार की जाती है।

VII. पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर सिफारिशें /

पारिवारिक पेंशन (अनुशंसा संख्या। 21. 1 से 21.4)

98. बढ़ती उम्र पर आवश्यक अतिरिक्त सहायता के कारण, केंद्र सरकार की पेंशन की अतिरिक्त मात्रा प्रदान करने की नीति रही है। आयोग ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V के भुगतान की सिफारिश की है।

99. यह देखा गया है कि अलग-अलग राज्यों में पेंशन और पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के अनुदान के लिए अलग-अलग उम्र होती है। 7 वें सी. पी. सी. ने न्यूनतम आयु के रूप में 80 वर्ष का सुझाव दिया। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी 80 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन मिलती है। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव बनर्जी ने तर्क दिया कि चूंकि जिला न्यायाधीश कम उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए उन्हें कम उम्र में भी पेंशन की अतिरिक्त राशि मिलनी चाहिए।

100. यह देखते हुए कि कई राज्यों ने 70 वर्ष की आयु से यह लाभ प्रदान किया और आयोग ने अतिरिक्त अनुदान की सिफारिश की। 75 वर्ष की आयु से पेंशन की मात्रा। आयोग के इस तर्क को स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि राज्य अधिक लाभकारी पेंशन दरें दे रहे हैं, तो न्यायिक अधिकारियों को इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायिक अधिकारियों को राज्य के अधिकारियों से बदतर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, यह न्यायालय इस सिफारिश को स्वीकार करता है।

101. आयोग ने आगे सिफारिश की है कि इस लाभ का भुगतान 01.01.2016 से किया जाए। वेतन और पेंशन के पहलुओं के लिए अन्य समान सिफारिशों के साथ, इस सिफारिश को स्वीकार किया जाता है।

102. आयोग की चिंता, अनुशंसा संख्या 21.3 में परिलक्षित होती है, कि उन अधिकारियों के खिलाफ वसूली शुरू की जाएगी जिन्हें

65 या 70 वर्ष की आयु से दी गई अतिरिक्त पेंशन वास्तविक है। यदि न्यायिक अधिकारियों को पहले ही अधिक लाभकारी शासन प्रदान किया जा चुका है और उन्हें आयोग द्वारा सुझाए गए शासन में स्थानांतरित कर दिया गया है और न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो उनके खिलाफ कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए। नतीजतन, यह राज्यों पर छोड़ दिया जाता है कि वे 75 वर्ष की आयु तक भी लाभ जारी रखें। इन सिफारिशों को तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

VIII. ग्रेच्युटी पर सिफारिशें (अनुशंसा संख्या। 21. 1 से 21.4)

103. आयोग द्वारा ग्रेच्युटी पर पहली सिफारिश है -

ग्रेच्युटी की गणना को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50 (1) (ए) के बराबर लाना। कोई विवाद नहीं हो सकता

इस सिफारिश के संबंध में क्योंकि यह सेवा की शर्तों में एकरूपता लाने के लिए है। इसलिए, यह सिफारिश इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य है।

104. आयोग ने आगे सिफारिश की कि सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान के लिए अधिकतम सीमा रु।

लाख जो [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब भी डीए में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो इसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह

7 वें सी. पी. सी. की रिपोर्ट के अनुसार भी सिफारिश की गई है, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीवन यापन की लागत बिना उद्देश्य के उपदान न बने। इसलिए, यह सिफारिश न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य भी है।

105. तीसरी सिफारिश 01.01.2016 से सिफारिशों को प्रभावी बनाना है। यह अब इस न्यायालय द्वारा पहले भी सुलझा लिया गया है और वर्तमान निर्णय में भी दोहराया गया है। द.

सिफारिशें 01.01.2016 से लागू होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, वे न्यायिक अधिकारी जो 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें भी रिपोर्ट की स्वीकृति से लाभ होना चाहिए। इस प्रकार, आयोग ने सुझाव दिया है कि संशोधित अधिकतम सीमा के अधीन उन्हें अंतर उपदान का भुगतान किया जाए। यह केवल परिणामी है और इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है।

अदालत। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

106. ग्रेच्युटी के विषय पर आयोग द्वारा की गई अंतिम सिफारिश यह है कि मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान 7 वें सी. पी. सी. की तर्ज पर किया जाए। तदनुसार, सिफारिश स्वीकार की जाती है क्योंकि यह इस न्यायालय द्वारा पहले से ही स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप है।

IX. सेवानिवृत्ति की आयु पर सिफारिशें

107. आयोग द्वारा न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में कोई बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है। अतः इस न्यायालय द्वारा इस विषय पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है।

X. के मामले में वित्तीय सहायता पर सिफारिशें

मृत्यु।

108. आयोग ने सिफारिश की है कि यदि किसी न्यायिक अधिकारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान मृतक अधिकारी के जीवनसाथी/आश्रित को देय है। आयोग की सिफारिश में है

सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 की शर्तें। यह सिफारिश उचित है और एकरूपता के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए है।

सेवाएँ। इसलिए, यह इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य है।

XI. पेंशनभोगियों की सहायता के लिए सिफारिशें

109. आयोग ने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को दी जाने वाली सहायता पर कुछ सुविचारित सिफारिशें की हैं। हालांकि वे स्वीकृति के योग्य हो सकते हैं, लेकिन बाद के चरण में उन पर

विचार करना उचित है क्योंकि उन्हें सिद्धांतों या सभी भारतीय न्यायाधीशों के संगठन में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.]

किसी भी नियम में संशोधन केवल कार्यकारी प्रकृति के होते हैं। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि सिफारिशों पर बाद में विचार किया जा सकता है।

बारहवीं। नई पेंशन योजना को समाप्त करने की सिफारिशें

110. इस न्यायालय को की गई सिफारिशों से अवगत कराया गया है।

न्यायिक अधिकारियों पर नई पेंशन योजना लागू न होने के संबंध में आयोग द्वारा। हालांकि, कई राज्यों द्वारा इस मुद्दे पर उठाई गई आपत्तियों को देखते हुए, राज्यों को सुनने के बाद इस मुद्दे पर अलग से विचार किया जा सकता है। इसलिए इस सिफारिश पर भी बाद में विचार किया जाएगा।

111. सिफारिशों पर परिणामी स्थिति सारणीबद्ध है।

सुविधा के लिए नीचे दिया गया है:

सिफारिशें

सिफारिशें

इ

स न्यायालय का आदेश

नहीं।

39.1

01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए पेंशन में कोई बदलाव नहीं-स्वीकार किया गया
पेंशन/पारिवारिक पेंशन 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत की दर से होगी।

सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की संशोधित पेंशन स्वीकार की जाएगी।

39.2

50 % अंतिम बार प्राप्त वेतन पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए रिपोर्ट में दिए गए फॉर्मूलेशन स्वीकार किए गए

पढ़िए

39.3

पुनरीक्षण: (i) के लिए लागू होने वाला 2.81 का गुणक कारक

द.

पेंशन; या (ii) पेंशनभोगियों को शुद्धिपत्र में उचित रूप से फिट किया जाएगा।

दिनांकित

जो भी अधिक हो
01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को स्वीकार किया जाएगा

39.4

पढ़िए

संबंधित चरण में काल्पनिक रूप से रखा गया।

के

साथ

द.

पत्र
मार्च, 2021

शुद्धि
दिनांकित।

स्वी

कृत निर्देशित

01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों के
लिए, यदि

39.5

द्वारा कोई परिणामी पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है

लागू

किया जाए

इसके निर्देशों के आधार पर संबंधित सरकार

तुरंत

माननीय न्यायालय, उक्त लाभ का विस्तार किया जाएगा

उन्हें पहले बिना किसी और देरी के।

बार में कई वर्षों के अभ्यास के लाभ स्वीकार किए गए

39.6

एच. जे. एस. की सीधी भर्तियों को दिया जाता है जो इससे पहले सेवानिवृत्त
हुए थे
01.01.2016 .

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए, स्वीकृत में कोई बदलाव का सुझाव नहीं दिया जाता है।

4.1

पारिवारिक पेंशन का वर्तमान प्रतिशत, अर्थात् यह होगा -
@ 30 % सेवानिवृत्ति के समय अंतिम रूप से प्राप्त वेतन

न्यायिक अधिकारी

पात्र परिवार को 30 प्रतिशत की दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

4.2

नियम 54 सी. सी. एस. (पेंशन) नियमों में दिए गए सदस्य

1972 पति या पत्नी के बराबर, मृत्यु के बाद

पति-पत्नी।

पारिवारिक पेंशन की मात्रा स्वीकृत में निर्धारित की जाएगी।

4.3

जिस तरह से पेंशन की मात्रा तय की जाती है।

आय सीमा, यदि कोई संबंध में किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित। के साथ स्वीकृत -

4.4

आश्रित परिवार के सदस्यों (पति या पत्नी के अलावा) को राज्यों की स्वतंत्रता के लिए

पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होना इससे कम नहीं होगा

अनु

दान

अधिक

Rs.30,000/- प्रति माह (तीस हजार रुपये प्रति माह)

लाभ

कारी स्थिति

महीना)।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा

21.1

स्वीकृत व्यक्ति के पूरा होने पर पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा

द्वितीय भाग-।

अतिरिक्त पेंशन का यह लाभ स्वीकृत व्यक्तियों को उपलब्ध होगा।

21.2

सभी पात्र पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी

01.01.2016 .

जिन लोगों ने स्वीकार किया है, उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी।

21.3

के मौजूदा आदेशों के अनुसार 65 या 70 वर्ष की आयु

कुछ राज्य सरकारें

राज्य सरकारें भी स्वीकार करना जारी रखने का विकल्प चुन सकती हैं।

21.4

75 वर्ष की आयु तक प्रचलित लाभों का विस्तार

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी भी।

गैरच्युटी

सेवानिवृत्ति उपदान की गणना स्वीकृत नियम के अनुसार की जाएगी।

8.1

50 (1) (क) सी. सी. एस. (पेंशन) नियम 1972।

सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु की अधिकतम सीमा स्वीकार की गई

8.2

ग्रैच्युटी रुपये होगी। 20 जो लाखों में बढ़ेगा।
जब भी डीए में 50 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

ये सिफारिशें स्वीकृत से प्रभावी होंगी।

8.3

01.01.2016 .

उन अधिकारियों के लिए जो 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और स्वीकार किए गए हैं

8.4

पूर्व-संशोधित वेतन के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान और

उस समय अधिकतम सीमा, अंतर उपदान

वेतन के संशोधन के कारण देय भुगतान किया जाएगा।

संशोधित अधिकतम सीमा के अधीन।

मृत्यु उपदान का भुगतान पी में तालिका के अनुसार किया जाएगा। 52 , खण्ड. स्वीकार किया गया।

8.5

II सेवा में अवधि के आधार पर अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ V.

संघ [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा,

न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु में कोई बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है।

मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता

सीसीएस के नियम 54 (3) के अनुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ

9.1

(पेंशन) नियम, जैसा कि दिनांकित अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है

19.09.2019 परिवार के सदस्यों तक इसका विस्तार किया जाएगा।
अन्य लाभ जैसे एकमुश्त अनुदान,

9.2

राज्यों में पहले से ही लागू आधिकारिक क्वार्टर आदि
मृत्यु उपदान के अलावा आवेदन करना जारी रखें।

पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को सहायता

प्रस्तुत करके उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

11.1

चिकित्सा बिलों को संसाधित करने के लिए उचित सहायता

2

पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी जो बहुत बूढ़े, कमजोर या

भिन्न रूप से सक्षम या रोगी उपचार से गुजर रहे हैं
गंभीर बीमारी

11.2

जिला न्यायाधीश इसके लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे।
आपात स्थिति में सुविधा प्रदान करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो लाइसनिंग कार्य

अस्पताल में भर्ती होना और चिकित्सा बिल प्राप्त करना

पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को तुरंत मंजूरी दे दी गई।

विशेष प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी सौंपी गई

11.3

पेंशनभोगियों/परिवार के अभ्यावेदन को संसाधित करना
पेंशनभोगी और कार्रवाई शुरू करने के लिए जिस पर विचार किया जा सकता है

उच्च न्यायालय में संयुक्त पंजीयक के पद का अधिकारी।
उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पर्यवेक्षण के लिए नामित किया जाएगा।

11.4

निर्देश दिए।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश संघों के प्रतिनिधि

11.5

के महापंजीयक से मिलने की अनुमति दी जाएगी
उच्च न्यायालय वर्ष में कम से कम एक बार इस पर चर्चा करता है
समस्याएँ, यदि कोई हों।

11.6

के आंकड़ों को संकलित करने के लिए उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री
पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)/परिभाषित 1

31.1

अंशदायी पेंशन योजना लागू नहीं होगी -

2

सभी न्यायिक अधिकारी।

परिभाषित लाभ पेंशन योजना/पुरानी पेंशन

31.2

यह योजना सभी न्यायिक अधिकारियों पर लागू होगी।
उनके न्यायिक सेवा में शामिल होने की तारीख चाहे जो भी हो
सेवा करते हैं।

31.3

जिनके पास 01.01.2004 के बाद न्यायिक सेवा है, उनके लिए उस पर अर्जित प्रतिफल के साथ योगदान

उन्हें वापस कर दिया जाएगा या उनके जी. पी. सी. में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

खाता।

सरकार जी. पी. एफ. खोलने की सुविधा प्रदान करेगी।

31.4

न्यायिक सेवा में नए प्रवेशकों का लेखा-जोखा

01.01.2004 और उनके योगदान के साथ हस्तांतरण उस पर अर्जित प्रतिफल।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. समान दिशा-निर्देश

112. अंततः, स्वीकृति का प्रभाव

इस न्यायालय की सिफारिशें हैं कि सभी क्षेत्राधिकारों में न्यायिक अधिकारियों के सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। इस प्रकार यह निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय और सक्षम प्राधिकारी, जहां भी लागू हो, नियमों को लागू करें।

उपरोक्त न्यायालय द्वारा 3 की अवधि के भीतर स्वीकार की गई सिफारिशें

महीनों तक। चार महीने के भीतर उच्च न्यायालयों, राज्यों और संघ द्वारा अनुपालन शपथ पत्रों को रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए।

113. वेतन के बकाया भुगतान के मामले में, इस न्यायालय ने 27.07.2022 और 18.01.2023 दिनांकित आदेशों द्वारा पहले ही निर्देश दिया था कि सभी बकाया

वेतन का भुगतान 30.06.2023 द्वारा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह निर्देश दिया जाता है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन शपथ पत्र दाखिल किए जाने चाहिए 30.07.2023 द्वारा कि वेतन के बकाया को सकारात्मक रूप से संबंधित अधिकारियों के खातों में जमा कर दिया गया है।

114. पेंशन की संशोधित दरें, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, 01.07.2023 से देय होंगी। पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, ग्रेजुटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया भुगतान के लिए, दिनांकित 27.07.2022 और 18.01.2023 के आदेशों का पालन करते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि 25 प्रतिशत का भुगतान 31.08.2023, अन्य 25 प्रतिशत का भुगतान 31.10.2023 और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान 31.12.2023 द्वारा किया जाएगा।

115. वेतन और पेंशन पर आगे अनुपालन के लिए 17.7.2023 पर सूची बनाएँ

यह न्यायालय किस तारीख को भत्तों पर सिफारिशों पर विचार करेगा।

निर्देश जारी किए गए।

दिव्या पांडे

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)